



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 2017/अग्रहायण 8, 1939

No. 450]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2017/AGRAHAYANA 8, 1939

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 21 नवम्बर, 2017

सं. टीएएमपी/58/2017-केओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, कोलकाता पत्तन न्यास से प्राप्त हल्दिया गोदी परिसर की 3सरी तेल जेटी में बर्थ हुए पोतों से किंगर जेटी को कॉमन प्रयोक्ता आधार पर 16" व्यास पाइपलाइन से खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए प्रशुल्क नियत करने के प्रस्ताव का संलग्न आदेश के अनुसार निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/58/2017-केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास

- - -

आवेदक

गणपूर्ति

(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(नवंबर, 2017 के 14वें दिन पारित)

यह मामला कोलकाता पत्तन न्यास से प्राप्त हल्दिया गोदी परिसर की 3सरी तेल जेटी में बर्थ हुए पोतों से कॉमन प्रयोक्ता आधार पर 16" व्यास पाइपलाइन से खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए प्रशुल्क नियत करने से संबंधित है।

2.1. केओपीटी द्वारा 10 जुलाई, 2017 के अपने प्रस्ताव में उठाये गए मुख्य मुद्दों का सारांश इस प्रकार है:-

- (i) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी भूमि नीति दिशानिर्देश यह व्यवस्था करते हैं कि किसी एक पार्टी द्वारा डाली गई कॉमन प्रयोक्ता पाइपलाइन का प्रयोग अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा भी सभी पक्षों और पत्तन न्यास मंडल के बीच स्वीकृत शर्तों और निबंधनों पर किया जा सकता है।

- (ii) मैसर्स एमामी एग्रीकल्चर लि. (ईएएल) ने केओपीटी बोर्ड द्वारा अनुमोदित हल्दिया तेल जेटी (एचओजी)- III से एचडीसी, केओपीटी की फिंगरजेटी तक 16" व्यास की खाद्य तेल पाइपलाईन बिछाई हैं। [केओपीटी द्वारा एचओजी-III से फिंगर जेटी तक 16" व्यास की एक पाइपलाईन बिछाने के लिए मार्गाधिकार अनुमति के अनुमोदन संबंधी बोर्ड के संकल्प की प्रति भेजी गई है।]
- (iii) भूमि नीति दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसरण में अधिकतर खाद्य तेल आयातकों और भंडार प्रचालकों ने मैसर्स ईएएल द्वारा तीसरी तेल जेटी पर बिछाई गई 16 इंच व्यास की पाइपलाईन का प्रयोग करना स्वीकार किया है। वे मैसर्स ईएएल को उक्त पाइपलाईन के प्रयोग पर 40/-रु. प्रति टन की भुगतान की शर्तों और निबंधनों पर भी सहमत हैं।
- (iv) न्यासी मंडल ने इस बारे में निबंधनों और शर्तों को 1 जुलाई 2016 के संकल्प संख्या आर/39/एचडीसी/ एडीएमएन/1/07/2016 के द्वारा अनुमोदन किया है। [के ओपीटी द्वारा निबंधनों और शर्तों के अनुमोदन के संकल्प की प्रति प्रस्तुत की है।]
- (v) इसके अतिरिक्त, भूमि नीति दिशानिर्देश बोर्ड की सहमति से किसी एक पक्ष द्वारा बिछाई गई पाइपलाईन का प्रयोग अन्यो द्वारा करने की शर्तों और निबंधनों का निर्णय करने के कार्यक्षेत्र की भी व्यवस्था करते हैं। ऐसी पाइपलाईन सुविधा के उपयोग की दर और अन्य शर्तों का अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि जेटियों से पाइपलाईन सुविधा का प्रयोग कार्गो प्रहस्तन प्रयोजनों से किया जाता है और उसका अनुमोदन बोर्ड ने 31.05.2017 के अपने संकल्प संख्या आर/283/एचडीसी/ एडीएमएन/3/05/2017 के द्वारा किया है। [बोर्ड के 31.05.2017 के संकल्प की प्रति केओपीटी द्वारा प्रस्तुत की गई है।]

2.2. प्रस्ताव की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं:

- (i) केओपीटी, एचडीसी गोदी के भीतर विभिन्न प्रकार के तरल कार्गो का प्रहस्तन करता है। वर्ष 2016-17 में, केओपीटी ने एचडीसी की इम्पाउंडेड डॉक के भीतर 486 पोतों से 3.96 मिलियन टन तरल कार्गो का प्रहस्तन किया।
- (ii) बर्थसंख्या 2, 8 और 13 में चल हार्बर क्रेनों की तैनाती के साथ एचडीसी की इम्पाउंडेड डॉक के भीतर हाल ही में शुष्क बल्क कार्गो प्रहस्तन क्षमता में 6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। शुष्क बल्क कार्गो की 6 मिलियन टन की इस अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने की दृष्टि से, इम्पाउंडेड डॉक के भीतर शुष्क बल्क कार्गो पोतों के प्रहस्तन में वृद्धि लाने की जरूरत है, जो इस समय लॉक गेट के कारण प्रतिबंधित है। इसलिए, केओपीटी ने खाद्य तेल पोतों का प्रहस्तन इम्पाउंडेड डॉक के बाहर करने का निर्णय लिया ताकि अतिरिक्त शुष्क बल्क कार्गो पोतों के प्रहस्तन के लिए इम्पाउंडेड डॉक के भीतर जगह बनायी जा सके।
- (iii) उक्त को ध्यान में रख कर मैसर्स ईएएल को तीसरी जेटी से फिंगर जेटी तक 16" व्यास की कॉमन प्रयोक्ता खाद्य तेल पाइपलाईन बिछाने की अनुमति दी गई थी। मैसर्स ईएएल ने फिंगर जेटी तक पाइपलाईन बिछा दी है। मैसर्स ईएएल और खाद्य तेल के अन्य उत्पादकों ने अपने-अपने फ्लैक्सिबल होसों को उक्त 16" व्यास की कॉमन प्रयोक्ता पाइपलाईन से जोड़ भी दिया है। भूमि नीति दिशानिर्देश अनुबद्ध करते हैं कि ऐसी पाइपलाईन सुविधाओं के प्रयोग की दरें और अन्य शर्तों प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए क्योंकि जेटियों से ऐसी पाइपलाईन सुविधा कार्गो प्रहस्तन प्रयोजन से प्रयोग में लायी जाती है।
- (iv) इस मामले में अन्य किसी संदर्भ शुल्क के अभाव में, प्रस्ताव 2008 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत दायर किया गया है जो प्रशुल्क के निर्धारण के लिए एकमात्र दिशानिर्देश उपलब्ध है।
- (v) दिशानिर्देशों के अनुसार, इष्टतम क्षमता का निर्धारण वर्ष में 255 दिनों के वास्तविक प्रचालन के आधार पर निर्धारित किया जाना होता है। तथापि, तीसरी तेल जेटी विभिन्न प्रकार के तरल कार्गो प्रहस्तन करती है जैसे कूड, नैपथा, पीओएल उत्पाद और खाद्य तेल। भविष्य में, इस जेटी पर एलपीजी भी प्रहस्तित की जायेगी। चूंकि मैसर्स ईएएल द्वारा बिछाई गई कॉमन प्रयोक्ता पाइपलाईन का उपयोग मात्र खाद्य तेलों के परिवहन के लिए किया जाता है क्योंकि इस पाइपलाईन के द्वारा खाद्य तेलों के अलावा अन्य किसी भी वस्तु को प्रवाहित नहीं किया जा सकता, यह मान लिया जाता है कि जेटी में एक महीने में औसतन 9 दिन को केवल खाद्य तेल पोत ही रहेंगे। इस प्रकार, इष्टतम क्षमता का निर्धारण एक वर्ष में 108 दिन की दर से किया जाना है, जैसा कि प्रतिमान नीचे दिये गए हैं:-

तीसरी जेटी में खाद्य तेल प्रहस्तन के प्रयोग में लाई गई पाइपलाईन के दिनों की संख्या	108 दिन
प्राधिकरण के दिशानिर्देश के अनुसार डिस्चार्ज दर	300 टन प्रति घंटा
निर्धारित इष्टतम क्षमता = 108 दिन x 300 टन प्रति घंटा x 24 घंटा	777600 टन

- (vi) **2016-17** के दौरान एचडीसी में प्रहस्तित खाद्य तेल पोतों के औसत पार्सल भार के आधार पर आकलित पोतों की संख्या यानी 8700 टन और 777600 टन की इष्टतम पाइपलाईन क्षमता।

आकलित इष्टतम क्षमता	777600 टन
2016-17 के दौरान एचडीसी में प्रहस्तित खाद्य तेल पोतों का औसत पार्सल भार	8700 टन
खाद्य तेल पोत (777600/8700)	89

- (vii) पूंजीगत लागत आकलन:

मैसर्स ईएएल द्वारा भेजा गया लागत व्यौरा, 30 मई, 2017 को चार्टरित अभियंता द्वारा विधिवत् प्रमाणित इस प्रकार है:-

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु. में)
1.	16 इंच एपीएल 5एल पाइप	22213170
2.	20 इंच ईआरडब्ल्यू सी क्लास केसिंग के लिए	556920
3.	24 इंच ईआरडब्ल्यू सी क्लास केसिंग के लिए	485100
4.	16 इंच सीमलैस लम्बे बैंड	308700
5.	16 इंच सीमलैस छोटे बैंड	81900
6.	16 इंच गेट वैल्यू क्लास 150 फ्लेज एंड	204750
7.	12 इंच गेट वैल्यू क्लास 150 फ्लेज एंड	173250
8.	8 इंच गेट वैल्यू क्लास 150 फ्लेज एंड	29400
9.	16 इंच एमएस फ्लैज क्लास 150, एसओआरई	7560
10.	12 इंच एमएस फ्लैज क्लास 150, एसओआरई	8508
11.	8 इंच एमएस फ्लैज क्लास 150, एसओआरई	2310
12.	रैपिंग कोटिंग ब्रिटुमैन टेप	1965600
	योग सामग्री लागत (क)	26037168
1	भूमि खुदाई	1791400
2	भूमि खुदाई (कड़ी जगह, हाथों से कटिंग)	416000
3	मिट्टी भराई	411750
4	क्षैतिज भेदक द्वारा सड़क क्रॉसिंग (20 मीटर से कम)	550000
	20 मीटर से 30 मीटर	780000
	30 मीटर से अधिक	1500000
5	पाइप स्थापन	10752000
6	पाइप जोड़ना	1570400
7	ऑनलाइन मद यानी वेल्यूज़	17600
8	रैपिंग कोटिंग	1936000
9	सामग्री उतरायी	174000

10	सर्वेक्षण लागत	250000
11	कैथोडिक संरक्षण	2500000
	सेवा कर पूर्व कुल सेवा लागत	22649150
	जोड़ें सेवा कर @ 15%	3397373
	सेवा कर पश्च योग सेवा लागत (ख)	26046523
	पाइप विद्युत की कुल लागत (क)+(ख) = (ग)	52083691
	एक बार की पर्यवेक्षण लागत (ग) का @ 15%	7812554
	कुल परियोजना लागत	59896245

(viii) प्रचालन लागत का आकलन 2008 के दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार है:

लागत की मद	अपनाया गया आधार	राशि (रु. में)
पाइपलाईन की मरम्मत और अनुरक्षण	प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजीगत लागत का 2% (59896245x2%)	1197924.90
बीमा	प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजीगत लागत का 1% (59896245x1%)	598962.45
मूल्यहास	प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजीगत लागत का 3.17% (59896245x3.17%)	1898710.97
अन्य व्यय	प्राधिकरण के अनुसार पूंजीगत लागत का 1%	598962.45
मार्गाधिकार शुल्क	वर्तमान दरमानों के अनुसार और किस भूमि के लिए मार्गाधिकार अनुमति दी गई है।	704718.00
प्रति पोत ईंधन लागत (पिग लांचर प्रचालन के लिए)	मैसर्स ईमामी द्वारा दिये गए आकलन के अनुसार प्रति पोत 120 लीटर (120 लीटर x 89 पोत @ 57.23 प्रति लीटर, इमामी द्वारा यथा आकलित)	611216.40
	कुल ओएंडएम लागत	5610495.17

(ix) कुल राजस्व अपेक्षा और कुल राजस्व अपेक्षा का संविभाजन:

मद	राशि (रु. में)
कुल ओएंडएम लागत	5610495.17
आरओसीई (पूंजीगत लागत का 16%)	9583399.20
कुल राजस्व अपेक्षा	15193894.37
पाइपलाईन द्वारा कार्गो प्रहस्तन प्रभार (95%)	14434199.65
विविध प्रभार (5%)	759694.72

(X) उक्त क्रिया के अनुसार केओपीटी प्रस्तावित दर पर निम्नानुसार पहुंचा है:

मद	निर्धारण का आधार	राशि
पाइपलाईन द्वारा कार्गो प्रहस्तन प्रभार (95%)	₹.14434199.65/777600 टन	₹.18.56 प्रति टन
विविध प्रभार (5%)	₹. 759694.72/89 पोत	₹.8536/- प्रति पोत

2.3. चूंकि इस मामले में 5682.15 मीटर लंबी खाद्य तेल पाइपलाईन के लिए 18.56/रु. प्रति टन की दर का आकलन किया गया है, अन्य बर्थों पर इसी प्रकार की पाइपलाईन के लिए अन्य प्रयोक्ता की कार्गो प्रहस्तन प्रभारों की दर 3.26/- रु. प्रति किलोमीटर प्रस्तावित है (18.56 रु./ 5.682 कि.मी)। प्रति पोत विविध व्यय 8536/- रु. प्रति पोत ही रहेंगे।

2.4. यह देखा जाता है कि, केओपीटी बोर्ड ने तीसरी जेटी से फिंगर जेटी तक कॉमन प्रयोक्ता पाइपलाईन के माध्यम से खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए 18.52 रु. प्रति मीट्रिक टन और पोत विविध प्रभार 8519 रु. प्रति पोत का भिन्न बर्थ से कॉमन प्रयोक्ता के माध्यम से खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए प्रभार 3.25 रु. प्रति मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर का अनुमोदन किया है। इस संदर्भ में केओपीटी ने बताया है कि खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए प्रस्तावित दर निकालने के लिए, ईंधन की संशोधित दर और मार्गाधिकार अनुमति शुल्क पर भी सुविचार किया गया है और कि संशोधित प्रस्तावित दर को बोर्ड की आगामी बैठक में सूचना के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा।

2.5. इस प्रकार केओपीटी का प्रस्ताव निम्नलिखित का अनुमोदन चाहता है:

- “(i) ‘खाद्य तेल’ की परिभाषा ‘खाद्य तेल’ का अर्थ पीएलएमओसी, सीबीओ, सोया तेल आदि (कच्चा और परिष्कृत दोनों ही) है।
- (ii) तीसरी तेल जेटी से फिंगर जेटी को 16" व्यास की कॉमन प्रयोक्ता खाद्य तेल पाइपलाईन के माध्यम से खाद्य तेल प्रहस्तन प्रभार:

क्र.सं.	वस्तु	यूनिट	राशि (रु. में)
1.	खाद्य तेल पाइपलाईन प्रयोग के प्रहस्तन प्रभार	प्रति मीट्रिक टन	18.56
2.	विविध प्रभार (पिगिंग आदि)	प्रति पोत	8536/-

- (iii) एचडीसी पर भिन्न बर्थों से कॉमन प्रयोक्ता खाद्य तेल पाइपलाईन के माध्यम से खाद्य तेल प्रहस्तन प्रभार (तीसरी तेल जेटी से फिंगर जेटी तक 16" व्यास की खाद्य तेल पाइपलाईन के अतिरिक्त):-

क्र.सं.	वस्तु	यूनिट	राशि (रु. में)
1.	खाद्य तेल पाइपलाईन प्रयोग का प्रहस्तन प्रभार	प्रति मीट्रिक टन प्रति कि.मी.	3.26
2.	विविध प्रभार (पिगिंग आदि)	प्रति पोत	8536/-

सामान्य टिप्पणी:

प्रशुल्क मुद्रास्फीति के प्रति सूचकांकित किया जायेगा परंतु 1 अप्रैल, 2014 और प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष की 1 जनवरी के बीच थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में परिवर्तन के 60% की सीमा तक। प्रशुल्क का ऐसा स्वतः समंजन प्रत्येक वर्ष होगा और समंजित प्रशुल्क सीमा संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी।”

3. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, केओपीटी के 10 जुलाई, 2017 के प्रस्ताव की प्रति हमारे 13 जुलाई 2017 के पत्र के द्वारा संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों (केओपीटी द्वारा दी गई सूची के अनुसार) को उनकी टिप्पणियां मांगने के लिए भेजी गई। प्रयोक्ताओं में से केवल 1 अर्थात् ईएएल ने 25 जुलाई, 2017 के ई-मेल के द्वारा अपनी टिप्पणी भेजी कि ईएएल प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता क्योंकि प्रस्तावित प्रशुल्क उनके लिए व्यवहार्य नहीं है। ईएएल द्वारा ऐसी ही टिप्पणियां संयुक्त सुनवाई के बाद भी भेजी गई। केओपीटी ने ईएएल की टिप्पणियों का प्रत्युत्तर दिया।

- 4.1. संदर्भित मामले में संयुक्त सुनवाई कोलकाता स्थित केओपीटी परिसर में 31 अगस्त, 2017 को हुई। संयुक्त सुनवाई में केओपीटी ने अपने प्रस्ताव का संक्षिप्त पावर-पाईंट प्रस्तुतीकरण दिया। केओपीटी और प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ताओं संगठनों ने अपने-अपने निवेदन रखे।
- 4.2. जैसा संयुक्त सुनवाई में निर्णय लिया गया था, कुछेक प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों ने अपनी-अपनी टिप्पणियां भेजीं। उन टिप्पणियों को फीड-बैक सूचना के रूप में केओपीटी को भेजा गया। केओपीटी ने 8 सितंबर, 2017 के अपने पत्र के द्वारा प्रत्युत्तर दिया।
5. केओपीटी के प्रस्ताव की संवीक्षा के आधार पर, केओपीटी से हमारे 4 अगस्त, 2017 के पत्र के द्वारा अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगे थे। केओपीटी ने अपने 8 सितंबर, 2017 के पत्र के द्वारा उत्तर दिया। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण और उस पर केओपीटी का उत्तर नीचे सरणीबद्ध किया जाता है:-

क्र.सं.	हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	केओपीटी का उत्तर
क.	सामान्य	
(i)	केओपीटी ने बताया है कि संशोधित प्रस्तावित दरें बोर्ड की आगामी बैठक में रखी जायेंगी। जैसा हमारे 13/7/2017 के पत्र के द्वारा पहले ही अनुरोध किया गया है केओपीटी को केओपीटी द्वारा यथाप्रस्तावित दरों पर बोर्ड के अनुमोदन की प्रति प्रस्तुत करनी है।	बोर्ड के संकल्प संख्या आर/331/एचडीसी/एडीएमएन/3/8/2017 दिनांक 17 अगस्त, 2017 प्रस्तुत है।
(ii)	हमने अपने 26 जुलाई 2017 के समसंख्यक पत्र के द्वारा इमामी एग्रेटेक लि. (ईएएल) से प्राप्त टिप्पणियां भेजी थीं और केओपीटी को ईएएल द्वारा किये गए निवेदन पर अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया था। केओपीटी को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करनी हैं।	केओपीटी ने सुनवाई के दौरान निवेदन किया था कि 3सरी तेल जेटी के वर्तमान उपयोगिता प्रतिमान को देखते हुए 0.78 मिलियन टन खाद्य तेल प्रहस्त करना संभव होगा। इसके लिए, पाइपलाइन उपयोगिता प्रभार उचित होना चाहिए। प्रयोक्ता वर्तमान में 40/-रु. प्रति टन के 3सरी तेल जेटी में खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए और अधिक उपयोग को बढ़ावा नहीं दे रहे। इसलिए 18.56 रु. का प्रस्तावित प्रभार से प्रयोक्ता 3सरी जेटी के उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। केओपीटी ने यह भी उल्लेख किया है कि प्रस्तावित दर 1 वर्ष के लिए लागू की जायेगी वशर्ते प्राधिकरण इस अवधि के दौरान खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए विभिन्ना प्रयोक्ताओं द्वारा 3सरी तेल जेटी के वास्तविक उपयोग के आधार पर समीक्षा की जाए।
(iii)	केओपीटी ने प्रस्ताव में बताया है कि खाद्य तेलों के आयातक और भंडार प्रचालक ईएएल द्वारा बिछाई गई 16" व्यास की खाद्य तेल पाइपलाइन का ईएएल को 40/-रु. प्रति टन के भुगतान पर प्रयोग करने को सहमत हैं। इस संबंध में, पत्तन का प्रस्ताव खाद्य तेल पाइपलाइन के प्रयोग के लिए 18.56 रु. के कार्गो प्रहस्तन प्रभार का अनुमोदन चाहता है, स्पष्ट नहीं है। केओपीटी ऊपर उल्लिखित दोनों लेखियों की किस्म को स्पष्ट करें।	मैसर्स ईएएल ने एचडीसी की एचओजे-III से फिंगर जेटी तक 16" व्यास की खाद्य तेल पाइपलाइन बिछाई है। एमओएस द्वारा जारी भू-नीति दिशानिर्देश यह उपबंध करते हैं कि पाइपलाइन, यथासंभव, कॉमन प्रयोक्ता आधार पर बिछाई जानी चाहिए। यदि कोई अन्य पक्ष उस पाइपलाइन का प्रयोग करना चाहता है तो उसे ऐसी शर्तों पर प्रयोग करने दिया जाये जो संबंधित पक्षों और पत्तन न्यास बोर्ड के बीच स्वीकार्य हों। भू-नीति दिशानिर्देशों के उक्त उपबंधों को ध्यान में रखकर, केओपीटी ने सभी संभावित पक्षों और ईएएल के साथ 14.06.2016 को एक बैठक आयोजित की, जहां यह स्वीकार किया गया कि ईएएल तीसरी तेल जेटी पर उसकी खाद्य तेल पाइपलाइन का प्रयोग 40/- रु. प्रति टन के भुगतान पर करने पर सभी प्रयोक्ता प्रयोग कर सकेंगे। केओपीटी बोर्ड भी इस पर सहमत था और उसे जून 2018 तक की अविध के लिए लागू किया जाना था। बोर्ड के 01.07.2016 के संकल्प की प्रति पत्तन द्वारा भेजी गई है। तत्पश्चात्, एचओजी-III स्थित ईएएल की पाइपलाइन सुविधाओं के प्रयोक्ताओं ने, उनके द्वारा पहले स्वीकृत, 40/-रु. प्रति टन की दर को कम करने के अनुरोध किये जाने लगे।

		<p>केओपीटी ने यह भी नोट किया कि यद्यपि भूमि नीति किसी एक पक्ष द्वारा बिछाई गई पाइपलाईन का प्रयोग बोर्ड की सहमति से अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयोग के निबंधनों और शर्तों पर किया जा सकता है, फिर भी, क्योंकि जेटियों से पाइपलाईन की सुविधा कार्गो प्रहस्तन प्रयोजन के लिए होती है और इस प्रकार, ऐसी कार्गो प्रहस्तन सुविधाओं के प्रयोग की दर और अन्य शर्तें प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।</p> <p>उक्त को ध्यान में रखकर केओपीटी ने, अंतरिक रूप से प्राधिकरण के संबंधित दिशानिर्देशों के आधार पर एचडीसी की एचओजी-III से फिंगर जेटी तक बिछाई गई खाद्य तेल पाइपलाईन के कॉमन प्रयोग के लिए उगाही योग्य प्रशुल्क/प्रभारों का परिकलन किया। यह दर 18.56 रु. प्रति टन निकली और बोर्ड ने इसी का अनुमोदन किया।</p>
(iv)	केओपीटी प्रमाणित करे कि सुविचारित पाइपलाईन के परिणाम में तकनीकी कारणों से और सुधार लाना संभव होगा जिससे पम्पिंग दर/ क्षमता/ प्रहस्तन दर पर प्रभाव पड़ता हो।	पुष्टि की जाती है क्योंकि संबंधित 16" व्यास (भूमिगत) की खाद्य तेल पाइपलाईन जून 2016 में पहले ही बिछाई जा चुकी है और तभी से प्रचालन में है। प्रस्तावित दरें इन्हीं 16" व्यास पाइपलाईनों के माध्यम से खाद्य तेलों के प्रहस्तन के लिए है।
(v)	केओपीटी पुष्टि करे कि प्रस्ताव में परिकलित 89 पोत प्रतिवर्ष की संख्या में ईएएल के लिए आये पोतों की संख्या भी शामिल है।	पुष्टि की जाती है।
(vi)	केओपीटी ने ईएएल को 16" व्यास की पाइपलाईन से अतिरिक्त पाइपलाईन बिछाने की अनुमति भी दी है। केओपीटी उन पाइपलाईनों के माध्यम से अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा ईएएल को छोड़कर, कार्गो प्रहस्तन के प्रशुल्क सूचित करे।	<p>अन्य पाइपलाईन जिनके लिए ईएएल को मार्गाधिकार अनुमति दी गई है 10" और 12" व्यास की हैं। ये सभी पाइपलाईन इम्पाउंडेड गोदी के भीतर भिन्न-भिन्न बर्थों से बिछाई गई हैं। जहां अन्य प्रयोक्ताओं की अपनी-अपनी पाइपलाईनें भी बिछी हुई हैं। इसलिए, इम्पाउंडेड गोदी के भीतर ईएएल की इन 10"/12" पाइपलाईनों के कॉमन प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ी और न ही कोई प्रस्ताव है।</p> <p>चूंकि ईएएल द्वारा तीसरी जेटी से बिछाई गई खाद्य तेल की यह एकमात्र पाइपलाईन है, इसलिए अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा इसके कॉमन प्रयोग का प्रस्ताव किया गया है।</p> <p>तथापि, विचाराधीन प्रशुल्क प्रस्ताव में, केओपीटी ने प्रति किलो मीटर प्रति टन आधार पर एकल दर का प्रस्ताव भी किया है जिसका प्रयोग विभिन्न पक्षों द्वारा बिछाई गई अन्य खाद्य तेल पाइपलाईनों के लिए किया जा सकता है और जो कॉमन उपयोग की लंबाई पर निर्भर करेगा।</p>
ख.	<p>इष्टतम क्षमता:</p> <p>केओपीटी द्वारा एक वर्ष में 108 दिवस उपयोग पर सुविचार करते हुए पाइपलाईन की इष्टतम क्षमता निकाली गई है। यह बताया गया है कि खाद्य तेल पोतों के आगमन की वर्तमान प्रवृत्ति पर आधारित है। यदि इस प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन होता है तो प्रशुल्क की समीक्षा करनी ही पड़ेगी।</p>	<p>यह स्वीकार किया जाता है कि तीसरी तेल जेटी पर अन्य तरल कार्गो की उच्च प्रमात्रा का प्रहस्तन किया जाता है जिन्हें खाद्य तेलों के पोतों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तीसरी जेटी में खाद्य तेल प्रहस्तन की सीमा के भविष्य में कम होने की संभावना है।</p> <p>उक्त को देखते हुए, केओपीटी ने सुनवाई के दौरान सुझाव दिया कि केओपीटी द्वारा प्रशुल्क प्रस्ताव में 0.78 मिलियन टन के वार्षिक कार्गो प्रस्ताव के आधार पर फिलहाल प्रशुल्क 1 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाये। केओपीटी के अनुसार, तीसरी जेटी में कार्गो प्रहस्तन की वर्तमान प्रवृत्ति के आधार पर एक वर्ष में 0.78 मिलियन टन खाद्य तेल का प्रहस्तन ही संभव है बशर्ते ईएएल द्वारा बिछाई गई पाइपलाईन के उपयोग प्रभार व्यापार को आकर्षक हों।</p>

		एक वर्ष की अवधि के दौरान खाद्य तेल प्रहस्तन की प्रवृत्ति के आधार पर यथाप्रस्तावित प्रशुल्क की समीक्षा की जा सकती है और यदि अपेक्षित हुआ, प्राधिकरण पिछली अवधि के अतिरिक्त/घाटे को ध्यान में रखकर प्रशुल्क के पुननिर्धारण पर विचार कर सकता है।
ग.	पूँजीगत लागत:	
(i)	केओपीटी द्वारा पूँजीगत लागत के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य मई 2017 के हैं। केओपीटी परीक्षण करे कि क्या पूँजीगत लागत जीएसटी शासन में भी वही रहेगी।	संबंधित पाइपलाईन ईएएल द्वारा जीएसटी लागू होने से पहले विद्यार्थी गई है। ईएएल द्वारा यथाप्रस्तुत और 2017 में चार्टरित लेखाकार फर्म द्वारा प्रमाणित पूँजीगत लागत परिकलनों में 15% की दर से सेवा कर तत्व जोड़ा गया है।
(ii)	598.96 लाख रु. की पाइपलाईन बिछाने की कुल परियोजना लागत में 520.83 लाख रु. की कुल लागत का 15% की एक बारगी पर्यवेक्षण लागत भी शामिल है। संभाव्यतः यह एक बारगी पर्यवेक्षण लागत ईएएल द्वारा केओपीटी को देनी है, जैसा भूमि नीति दिशानिर्देशों में उपबंधित है। केओपीटी परीक्षण करे कि क्या प्रतिफल के अनुमत के प्रयोजन से पूँजीगत लागत में एक-बारगी पर्यवेक्षण प्रभार सही हैं।	एक बारगी पर्यवेक्षण प्रभार भूमि नीति दिशानिर्देशों के अनुसार पाइपलाईन बिछाने के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए अदा की गई है। इस प्रकार, केओपीटी ने इसे परियोजना लागत के भीतर सुविचार किया है।
(iii)	केओपीटी नोट करे कि यद्यपि पिग लांचर के परिचालन के लिए ईंधन लागत को हिसाब में लिया गया है, पिग लांचर की पूँजीगत लागत को परियोजना लागत में जोड़ा गया प्रतीत नहीं होता।	पिगिंग संबंधित पाइपलाईन प्रयोक्ताओं द्वारा किये जाने, जैसा कि सुनवाई के दौरान प्रयोक्ताओं द्वारा संकेत दिया गया था, को ध्यान में रखकर पिगिंग के लिए ईंधन लागत और पाइपलाईन उपयोगिता प्रभार के लिए 100% लागत को छोड़कर और पिगिंग आदि के अभाव में विविध प्रभारों के लिए कोई प्रावधान किये बिना उपयोग प्रभार प्रशुल्क का पुननिर्धारण किया गया है। पुननिर्धारित प्रशुल्क 18.75 रु. प्रति टन निकला है। केओपीटी ने परिकलन प्रस्तुत किया है। प्रति पोत 8536/-रु. के 'विविध प्रभारों' का तत्व पहले पिगिंग व्यवस्था के लिए प्रस्तावित किया गया था। अब इसे वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है।
घ.	प्रचालन लागत:	
(i)	केओपीटी पुष्टि करे कि पाइपलाईन की लागत पर 3.17% का सुविचारित मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों पर आधारित है।	पुष्टि की जाती है।
(ii)	केओपीटी मार्गाधिकार अनुमति के लिए लाइसेंस शुल्क का परिकलन, क्षेत्र दर्शाने के साथ-साथ मार्गाधिकार शुल्क का व्यौरा प्रस्तुत करे। सुविचारित किराया अनुसूची का संदर्भ भी बताया जाए।	केओपीटी द्वारा परिकलन प्रस्तुत हैं।
(iii)	(क) केओपीटी स्पष्ट करे कि पिग लांचर के परिचालन की लागत परिचालन लागत आकलन में प्रासंगिक है। (ख) प्रति पोत 120 लीटर की पिग लांचर के परिचालन में ईंधन लागत पर सुविचार करने का आधार दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित किया जाए। (ग) परिकलन में सुविचारित ईंधन की लागत के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें।	पिगिंग लागत के तत्व को हटा दिया गया है और प्रशुल्क नए सिरे से प्रस्तावित किया गया है और वह 18.75 रु. प्रति टन निकलता है। केओपीटी द्वारा परिकलन प्रस्तुत किया जाता है।

ड.	प्रहस्तन प्रभार/विविध प्रभारों का परिकलन	
	'प्रति टन' आधार के स्थान पर 'प्रति पोत' आधार पर विविध प्रभारों के निर्धारित के कारणों का औचित्य बताएं।	उपरोक्तानुसार
च.	दरमान:	
(i)	केओपीटी का प्रस्ताव ईएएल द्वारा विद्ययी गई 16" व्यास की खाद्य तेल पाइपलाइन के प्रयोग के प्रभारों की उगाही करने से संबंधित है। समान प्रहस्तन प्रभार को आधार के रूप में लिया गया है और 16" व्यास पाइपलाइन के अलावा खाद्य तेलों के प्रहस्तन के लिए निर्धारित है। केओपीटी स्पष्ट करे कि 3.26 रु. प्रति एमटी की प्रस्तावित दर ठीक रहेगी यदि 16" व्यास की पाइपलाइन से भिन्न हो।	<p>प्रस्तावित प्रशुल्क एचओजी-III से फिंगर जेटी तक विद्ययी गई 16" व्यास की खाद्य तेल कामन प्रयोक्ता पाइपलाइन के लिए एचडीसी पर विभिन्न अन्य जेटियों की विभिन्न प्रयोक्ताओं द्वारा खाद्य तेल पाइपलाइनों के कॉमन उपयोग के लिए दर निकालने के लिए आधार के रूप में सुविचार किया गया है।</p> <p>16" से कम व्यास की पाइपलाइनों के मामले में, पूंजीगत लागत कम होने की प्रत्याशा होती है। साथ ही, 16" पाइपलाइन की प्रवाह दर भी कम होने की प्रत्याशा होती है और इस प्रकार लागत प्रति टन प्रति कि.मी. समान रहने की संभावना होती है। इस परिकल्पना पर 3.26 रु. प्रति टन प्रति कि.मी. की दर (पुनः परिकलन पर 3.30 रु. प्रति टन प्रति कि.मी.) का प्रस्ताव व्यास पर ध्यान दिये बिना सभी खाद्य तेल पाइपलाइनों के कॉमन उपयोग के लिए किया गया है।</p>
(ii)	'प्रहस्तन प्रभारों' और 'विविध प्रभारों' के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सूची बाह्य करना होगा और प्रभारों के प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत अलग से दर्शाना होगा।	<p>यह सुविचार करते हुए कि पिगिंग आदि संबंधित प्रयोक्ताओं द्वारा की जानी है, दरमानों को पुनः परिकलित किया गया है। अब 'प्रहस्तन प्रभार' के स्थान पर 'पाइपलाइन उपयोग प्रभार' के रूप में प्रशुल्क नियत करने का प्रस्ताव है। सुनवाई के दौरान प्रयोक्ताओं द्वारा किये गए निवेदनों के आधार पर 'विविध प्रभारों' का कोई प्रस्ताव नहीं है।</p> <p>तदनुसार, प्रस्तावित उपबंध 31.12.2016 के राजपत्र संख्या 457 में अधिसूचित केओपीटी के दरमानों में भाग-IX (अधिकृत सेवा प्रदाताओं के लिए प्रभार) के अंतर्गत अंतर्विष्ट करने के लिए निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है:</p> <p>(i) 'खाद्य तेल की परिभाषा': खाद्य तेल का अर्थ पीएलएमओसीएसबीओ, सोया तेल आदि से है (कच्चा और परिष्कृत दोनों)</p> <p>(ii) 3सरी जेटी से फिंगर जेटी तक कॉमन प्रयोक्ता 16" व्यास खाद्य तेल पाइपलाइन के माध्यम से खाद्य तेलों के प्रहस्तन के लिए पाइपलाइन प्रयोग प्रभार 18.75 रु. प्रति मीट्रिक टन।</p> <p>(iii) एचडीसी पर विभिन्न बर्थों से कॉमन प्रयोक्ता खाद्य तेल पाइपलाइनों के माध्यम से खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए पाइपलाइन प्रयोक्ता प्रभार (3सरी जेटी से फिंगर जेटी तक 16" व्यास की खाद्य तेल पाइपलाइनों के माध्यम को छोड़कर): 3.30 रु. प्रति मीट्रिक टन प्रति कि.मी. अथवा उसका एक भाग।</p>
(iii)	यह मानते हुए कि पूंजीगत लागत और परिचालन लागत आकलन वर्ष 2017 की प्रचलित दरों पर सुविचारित की गई है। पत्तन द्वारा प्रस्तावित सामान्य टिप्पणी में 60% सूचकांकन लागू करने के आधार के रूप में वर्ष 2014 पर सुविचार करने के कारण स्पष्ट किये जाएं।	<p>वर्ष 2014 गलती से लिखा गया है। सूचकांकन खंड को निम्नवत् आशोधित किया जाता है:-</p> <p>प्रशुल्क स्फीति के प्रति सूचकांकित किया जायेगा परंतु 1 अप्रैल, 2017 और संगत वर्ष की 1 जनवरी के बीच थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में परिवर्तन के 60% की सीमा तक। प्रशुल्क का ऐसा स्वतः समंजन प्रत्येक वर्ष होगा और समंजित प्रशुल्क सीमा संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी।</p>

(iv)	सूचकांकन के प्रयोजन से, केओपीटी को निष्पादन मानकों का प्रस्ताव करना होगा।	चूंकि प्रशुल्क पाइपलाइन के कॉमन उपयोग के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है, जो पम्पिंग दर आदि से मुक्त है, इसलिए किसी निष्पादन मानक का प्रस्ताव नहीं किया गया है। डब्ल्यूपीआई आधारित सूचकांकन अनुरक्षण आदि में होने वाली विभिन्न लागतों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर प्रस्तावित किया गया है।
------	---	--

6. ऐसा प्रतीत होता है कि, केओपीटी ने अपने 8 दिसंबर, 2017 के अपने पत्र के द्वारा अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजते समय, अपने प्रस्ताव की समीक्षा की है। संशोधन प्रति पोत ईंधन लागत के लिए प्रचालन लागत को हटा देने की सीमा तक है (पिग लांचर प्रचालन के लिए), जिस पर केओपीटी ने अपने आरंभिक प्रस्ताव में विचार किया था। इसके अतिरिक्त, वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) को प्रहस्तन (95%) और विविध (5%) को अलग-अलग दर्शाने के प्रति, जैसा केओपीटी ने अपने आरंभिक प्रस्ताव में प्रस्तावित किया था, अब केओपीटी ने पिगिंग आदि के अभाव में विविध प्रभागों के लिए कोई प्रावधान किये बिना 100% एआरआर प्रहस्तन प्रभागों से वसूल करने का प्रस्ताव रखा है। उक्त समीक्षा को ध्यान में रखकर केओपीटी द्वारा आरंभिक प्रस्ताव में 18.56 रु. प्रति एमटी के प्रशुल्क का पत्तन ने पुनः आकलन करके 18.75 रु. प्रति एमटी कर दिया है।

7.1. केओपीटी के 8 दिसंबर 2017 के द्वारा प्रस्तुत सूचना और ईएएल द्वारा किये गए निवेदनों पर केओपीटी की टिप्पणियों की संवीक्षा करने पर केओपीटी द्वारा प्रस्तुत सूचना में कुछ अंतर पाये गए हैं। तदनुसार, हमने अपने 28 सितंबर, 2017 के पत्र के द्वारा केओपीटी से कुछ सूचना/ स्पष्टीकरण मांगे। केओपीटी ने अपने 27 अक्टूबर, 2017 के पत्र के द्वारा उत्तर दिया। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/ स्पष्टीकरण और केओपीटी के उत्तर को नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:

क्र.सं.	हमारे द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण	केओपीटी का उत्तर
(i)	केओपीटी द्वारा प्रस्तावित दरों को बोर्ड के अनुमोदन के संकल्प की प्रति, केओपीटी द्वारा संलग्न की गई बतायी गई है, वह केओपीटी के पत्र के साथ संलग्न नहीं पायी गई। उसे प्रस्तुत करें।	बोर्ड के 17.08.2017 के संकल्प संख्या आर/33/एचडीसी/एडीएमएन/3/8/2017 की प्रति के ओपीटी द्वारा भेजी गई है जिसमें तब तक 40/-रु. प्रति एमटी की प्रहस्तन दर जारी रखने की बात कही गई है जब तक नई दर को प्राधिकरण अनुमोदित और अधिसूचित नहीं कर देता।
(ii)	40/-रु. प्रति एमटी की दर के संबंध में केओपीटी का कहना है कि केओपीटी द्वारा 14-15 जून, 2016 को संभावित प्रयोक्ताओं और ईएएल के बीच आयोजित की गई बैठक में यह सहमति बनी थी कि सभी प्रयोक्ता खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए ईएएल की पाइपलाइन के प्रयोग 40/- रु. प्रति एमटी का भुगतान करेंगे। केओपीटी ने यह भी बताया है कि इसे केओपीटी बोर्ड ने भी स्वीकार किया था और उसे जून 2018 तक एक वर्ष की अवधि के लिए जारी रखा जायेगा। इस संबंध में केओपीटी निम्नलिखित सूचना की अपेक्षा है:	
(क)	40/- रु. प्रति एमटी की दर निकालने का आधार /लागत संबंधी ब्यौरा/ प्रकिया।	प्रयोक्ताओं के साथ ईएएल और केओपीटी द्वारा 14.06.2016 तथा 15.06.2016 को आयोजित बैठक कार्यवृत्तों से यह देखा जा सकता है कि 40/-रु. प्रति टन की दर विस्तार से चर्चा के बाद निकाली गई थी। संयोगवश, 40/- रु. प्रति एमटी की दर का सुझाव ईएएल द्वारा दिया गया था जिसे विस्तार से चर्चा के बाद विभिन्न प्रयोक्ताओं ने स्वीकार कर लिया।
(ख)	यह सुविचार करते हुए कि केओपीटी द्वारा प्रस्तुत बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए इस सुविधा के प्रयोग के लिए आरंभ में ईएएल को 40/- रु. प्रति एमटी की राशि का भुगतान करने पर जून 2016 में सहमत थे तो अब संयुक्त सुनवाई के दौरान 40/- रु. प्रति एमटी की उक्त उगाही का विरोध करना स्पष्ट नहीं होता। दर को कम करने के उनके अनुरोध के कारण बताए जाएं।	प्राधिकरण द्वारा आयोजित सुनवाई में कॉमन प्रयोक्ता पाइपलाइन के प्रयोक्ताओं ने यह बताया कि 2015 में तत्समय उन्होंने 40/- रु. प्रति एमटी की दर को एचडीसी पर बर्थिंग पूर्व रुकने की अत्यधिक अवधि (पीबीडी) के कारण विलंब शुल्क और कि यह दर 2 वर्ष की अस्थायी अवधि के लिए है जिसके भीतर इसकी समीक्षा की जायेगी को देखते हुए स्वीकार किया था, यद्यपि वह अधिक थी। प्रमुख उपयोक्ताओं ने भी तीसरी तेल जेटी पर खाद्य तेल प्रहस्तन की ऊंची दर के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी।

(ग)	केओपीटी बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर केओपीटी ने 2 जून 2016 से जून 2018 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए 40/- रु. प्रति एमटी की दर पहले ही लागू कर रखी है। इस स्थिति में यदि 18.75 रु. प्रति एमटी की दर, पत्तन द्वारा यथाप्रस्तावित, का अनुमोदन किया जाता है तो 18.75 रु. प्रति एमटी की प्रस्तावित दर की वैधता अवधि सूचित की जाये।	पाइपलाइन प्रयोग के लिए प्रशुल्क को वर्तमान दरमानों के भाग IX खंड 4 (अधिकृत सेवा प्रदाताओं के लिए प्रभार) के अंतर्गत अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव है (13.12.2016 को राजपत्र संख्या 457 में अधिसूचित केओपीटी के दरमानों में)। इस प्रकार, पाइपलाइन प्रयोग की प्रस्तावित दरें केओपीटी के वर्तमान दरमानों की वैधता की तारीख तक वैध होंगे।									
(घ)	केओपीटी ने इस आधार पर निष्पादन मानकों का प्रस्ताव नहीं किया है कि प्रशुल्क पाइपलाइन के कॉमन उपयोग के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है, जो पम्पिंग दर आदि से मुक्त है, इसलिए किसी निष्पादन मानक का प्रस्ताव नहीं किया गया है। डब्ल्यूपीआई आधारित सूचकांकन अनुरक्षण आदि में होने वाली विभिन्न लागतों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 9.1 और 9.3 का संदर्भ लिया जाता है जो पत्तन से सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त किये जाने वाले निष्पादन मानक प्रस्तावित करने की अपेक्षा करता है और कि प्रशुल्क का सूचकांकन महापत्तन न्यासों द्वारा प्रतिबद्ध निष्पादन मानकों की प्राप्ति के अधीन होगा और यह कोई पत्तन विशेष निष्पादन मानक प्राप्त नहीं करता है तो आगामी वर्ष में सूचकांकन की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस प्रकार, केओपीटी को यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि निष्पादन मानक निर्धारित न करने की स्थिति में प्रशुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा और आगामी अवसर पर पूर्ण समीक्षा तक स्थिर रहेगा। ऐसे परिदृश्य में, डब्ल्यूपीआई सूचकांकन संबंधी सामान्य टिप्पणी जैसा पत्तन द्वारा अपने प्रारूप दरमानों में प्रस्ताव किया है, तर्कसंगत नहीं हो सकता।	खाद्य तेल के निष्पादन मानक सीपीओ/आरडीबी, पॉम तेल/सीडीएसओ/सूरजमुखी तेल पर औसत 300 एमटी प्रति घंटा रखा जा सकती है। यह प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित निष्पादन मानकों के अनुरूप है।									
(ङ)	मार्गाधिकार अनुमति के लाइसेंस शुल्क, परिकलन के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया और क्षेत्र के साथ-साथ मार्गाधिकार शुल्क तथा किराया अनुसूची का संदर्भ देते हुए ब्यौरा पत्तन द्वारा केओपीटी के पत्र के साथ संलग्न सूचित किया गया है। परंतु वह नहीं मिला। कृपया प्रस्तुत करें।	3सरी जेटी से फिंगर जेटी तक 16" व्यास के बारे में मार्गाधिकार अनुमति प्रशुल्क का परिकलन दर्शाने वाला विवरण केओपीटी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।									
(iii)	इसके अतिरिक्त, ईएएल द्वारा अपने 4 सितंबर, 2017 के पत्र के द्वारा भेजी गई टिप्पणियों को हमारे 6 सितंबर, 2017 के समसंख्यक पत्र द्वारा केओपीटी को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। ऐसा देखा गया है कि केओपीटी ने ईएएल द्वारा किये गए निवेदनों पर कोई टिप्पणियां नहीं दी गई प्रतीत होती हैं, विशेष कर एचओजी III पर खाद्य तेल की अधिकतम मात्रा के 4 लाख टन प्रति वर्ष और 39.64 रु. प्रति एमटी संबंधी निवेदनों पर कोई उत्तर नहीं दिया, जैसा ईएएल ने सुझाव दिया था और जिसके समर्थन में ईएएल ने परिकलन संलग्न किया था।	ईएएल के 04.09.2017 के पत्र का परीक्षण किया गया। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि एचओजी- III की अधिकतम खाद्य तेल क्षमता पीओएल यातायात में प्रक्षेपित वृद्धि और 2018 के मध्य से एलपीजी प्रहस्तन को देखते हुए 6 दिन ही उपयोग में लाई जा सकती है। उस स्थिति में, खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए 3सरी जेटी की इष्टतम क्षमता 0.5184 मिलियन टन होगी (वर्ष में 72 दिन X 300 एमटी प्रति टन X 24 घंटे)। ऐसी स्थिति में प्रशुल्क 28.13 रु. प्रति टन बनता है जैसा नीचे बताया गया है:- <table border="1" data-bbox="820 1717 1414 1938"> <thead> <tr> <th>क्र.सं</th><th>विवरण</th><th>राशि (रु. में)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>इस पाइपलाइन के माध्यम से इष्टतम कार्गो यातायात एमटी में (6 दिन x 300 टन x 24 घंटे x 12 महीने)</td><td>518400</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>5.7 कि.मी पाइपलाइन विछाने की पूंजीगत लागत, जैसी ईएएल ने दी है।</td><td>5,98,96,245</td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं	विवरण	राशि (रु. में)	1.	इस पाइपलाइन के माध्यम से इष्टतम कार्गो यातायात एमटी में (6 दिन x 300 टन x 24 घंटे x 12 महीने)	518400	2.	5.7 कि.मी पाइपलाइन विछाने की पूंजीगत लागत, जैसी ईएएल ने दी है।	5,98,96,245
क्र.सं	विवरण	राशि (रु. में)									
1.	इस पाइपलाइन के माध्यम से इष्टतम कार्गो यातायात एमटी में (6 दिन x 300 टन x 24 घंटे x 12 महीने)	518400									
2.	5.7 कि.मी पाइपलाइन विछाने की पूंजीगत लागत, जैसी ईएएल ने दी है।	5,98,96,245									

		3.	खाद्य तेल पोतों का औसत पार्सल आकार एमटी में (एचडीसी में 2016-17 के औसत खाद्य तेल पार्सल आकार)	8700
			खाद्य तेल पोतों की कुल संख्या प्रति वर्ष (777600 / 8700=89.38 यानी 89)	89
		4.	परिचालन लागत	
		क	पाइपलाइन की मरम्मत और अनुरक्षण पूंजीगत लागत का @ 2%	1197924.90
		ख	बीमा मरम्मत और अनुरक्षण पूंजीगत लागत का @ 1%	598962.45
		ग	मूल्यह्रास मरम्मत और अनुरक्षण पूंजीगत लागत का @ 3.17%	1898710.97
		घ	मार्गाधिकार अनुमति के लिए लाइसेंस शुल्क प्रति वर्ष (संशोधित किराया अनुसूची के अनुसार कलेंडर वर्ष 2016 के लिए)	704718.00
		ङ	अन्य व्यय पूंजी लागत का @ 1%	598962.45
			कुल लागत	4999278.77
		5.	आरओसीई पूंजीगत लागत का @ 16%	9583399.20
		6.	कुल राजस्व अपेक्षा (रु. में)	14 82677.97
		7.	पाइपलाइन उपयोग प्रभार प्रति एमटी रु. में	28.13
		8.	एचडीसी में बिछाई गई अन्य खाद्य तेल पाइपलाइनों के पाइप लाइन उपयोग प्रभार प्रति एमटी रु. में	4.95

7.2. जैसा ऊपर बताया गया है, केओपीटी ने 23 अक्टूबर, 2017 के अपने पत्र के द्वारा अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजते समय, केओपीटी ने अपने प्रस्ताव की पुनः समीक्षा कर दी प्रतीत होती है। समीक्षा इस हद तक है कि पीओएल यातायात में प्रक्षेपित वृद्धि और वर्ष 2018 के मध्य से एलपीजी का प्रहस्तन आरंभ करने को ध्यान में रखकर यह बताया गया है कि इनका प्रभाव खाद्य तेल यातायात पर पड़ेगा खाद्य तेल पोत आकूपैसी को 108 दिन से घटा कर वर्ष में 72 दिन कर दिया है। उक्त समीक्षा को देखते हुए केओपीटी द्वारा सितंबर, 2017 में 18.75 रु. प्रति एमटी का प्रस्तावित प्रशुल्क अब पुनः परिकलन में 28.13 रु. प्रति एमटी किया गया है।

8. इस मामले के परामर्श से संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों और उन पर दिये गए तर्कों के उद्धरण संबंधित पक्षों को अलग से भेजे जायेंगे। ये ब्यौरे हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

9. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति उभार कर सामने आती है:

- कोलकता पत्रन न्यास (केओपीटी) के हल्दिया डॉक परिसर (एचडीसी) में बर्थ संख्या 2, 8 और 13 पर चल हार्बर क्रेनों की तैनाती से एचडीसी इम्पाउंडेड गोदी के भीतर शुष्क बल्क कार्गो प्रहस्तन की क्षमता में वृद्धि हुई है। इम्पाउंडेड डॉक के भीतर और ज्यादा शुष्क बल्क कार्गो प्रहस्तन के उद्देश्य से, केओपीटी ने खाद्य तेलों का प्रहस्तन इम्पाउंडेड गोदी से बाहर से प्रहस्तन करने का निर्णय लिया है ताकि इम्पाउंडेड गोदी के भीतर अतिरिक्त शुष्क बल्क कार्गो पोतों के प्रहस्तन के लिए स्थान बनाया जा सके। इस संबंध में केओपीटी ने हल्दिया तेल जेटी (एचओजी)- III से एचडीसी की फिंगर जेटी तक 16" व्यास की पाइपलाइन बिछाने का काम एक खाद्य तेल प्रयोक्ता नामतः मैसर्स ईमामी अग्रोटैक लिमिटेड (ईएएल) को सौंपा जिसका प्रयोग कॉमन प्रयोक्ता आधार पर किया जायेगा।
- केओपीटी ने बताया है कि ऐसी पाइपलाइन सुविधाओं के उपयोग की दर और अन्य शर्तें भूमि नीति दिशानिर्देशों के अनुसार इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की जायेंगी क्योंकि जेटियों से पाइपलाइन सुविधाओं का प्रयोग कार्गो प्रहस्तन

प्रयोजन के लिए किया जाना है। इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संशोधित भूमि नीति दिशानिर्देश, 2014 के ऐसा कोई उपबंध प्रतीत नहीं होता जिसके अंतर्गत इस प्राधिकरण को पाइपलाइनों के प्रयोग की दर नियत करने की अपेक्षा की गई है। तथापि, इस संबंध में, यह बताया जाता है कि केओपीटी ने खाद्य तेल की मूवमेंट एचओजी से फिंगर जेटी को करने की संकल्पना की है। दूसरे शब्दों में, एचओजी से फिंगर जेटी को खाद्यतेल की मूवमेंट किसी बार्फ, क्वे, जेटी आदि में अथवा पत्तन की सीमाओं या पत्तन अप्रोचों के भीतर किसी स्थान पर पोत से कार्गो की उतरायी के समान है। चूंकि परिचालन एचओजी पर पोत से कार्गो की फिंगर जेटी को मूवमेंट से संबंधित है, यह महापत्तन न्यास अधिनियम (एमपीटी) की धारा 42 के अंतर्गत सूचीबद्ध सेवाओं में से एक है।

ऐसे मामलों में जहां प्राधिकार धारा पर 42 (3) के अंतर्गत बीओटी रियायत करार से इतर किसी अन्य प्रकार से हो, प्रशुल्क नीति 2015 का खंड 9 इस प्राधिकरण से यह अपेक्षा करता है कि यह संबंधित पत्तनों पर कॉमन रूप से प्रयोग में आने वाली ऐसी सेवाओं की, सेवा प्रदाता के बिना किसी हवाले से, अधिकतम दरों का नियतन करे। इस प्रयोजन के लिए, इन प्रभारों को विनियमित कराने का प्रस्ताव संबंधित महापत्तन न्यास द्वारा आरंभ किया जायेगा और इस प्रकार यथा निर्धारित प्रशुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा चाहे ऐसा पत्तन द्वारा स्वयं प्रदान की जा रही हो या सेवाएं प्रदान करने की अनुमति निजी प्रचालक के दी हो।

केओपीटी ने प्रशुल्क निर्धारण के लिए अपना प्रस्ताव अप्रकट प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देश 2008 के अंतर्गत किया है। 2008 के दिशानिर्देश वहां प्रशुल्क नियतन के लिए लागू होते हैं जहां प्राधिकार बीओटी व्यवस्था के अंतर्गत हो। संदर्भाधीन मामले में केओपीटी ने ईएएल को कामन प्रयोक्ता पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी है। केओपीटी का प्रस्ताव यह नहीं बताता कि क्या केओपीटी और ईएएल के बीच यह प्रस्ताव बीओटी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त केओपीटी ने प्रशुल्क निर्धारण का प्रस्ताव अपने वर्तमान दरमानों में जोड़ने का किया है। पत्तन के वर्तमान दरमानों में प्रशुल्क निर्धारण तभी किया जा सकता है जब इन्हें प्रशुल्क नीति, 2015 के आधार पर निर्धारित किया जाये। प्रशुल्क नीति, 2015 के आधार पर तभी निर्धारित किया जा सकता है जब उनमें निर्धारित दो अप्रोचों का अनुपालन किया जाये अर्थात् वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) मॉडल, जिसमें पिछले वास्तविकों को हिसाब में लिया जाता है अथवा प्रशुल्क नीति के खंड 9 में निर्धारित विधि द्वारा। चूंकि केओपीटी का प्रस्ताव एआरआर मॉडल पर आधारित नहीं है, इसलिए इस पर प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 9 के अंतर्गत सुविचार किया जा सकता है।

प्रसंगवश, केओपीटी के 2010 में, केओपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव के आधार पर, सामान्य संशोधन प्रस्ताव का निपटान करते समय, एचडीसी की बर्थ संख्या 2 और 8 पर चल हार्बर क्रेन के उपयोग के प्रभारों को केओपीटी के दरमानों में लागू किया गया था, यद्यपि केओपीटी ने उसकी ओर से इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए ठेकेदारों को लगा दिया था। इसके अतिरिक्त, केओपीटी के विद्यमान दरमान वर्ष 2010 के बाद संशोधित किये गए थे और उनमें बर्थ संख्या 5/ऑफ 5/6/ऑफ 6 पर बर्थ हुए पोतों से खाद्य तेलों की उतरायी के लिए, एचडीसी पर शुल्क बल्क कार्गो के प्रहस्तन, पोतांतरण सुविधा, फ्लोरिंग क्रेन द्वारा कार्गो स्थानांतरण प्रभार के लिए अधिकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा उगाहे जाने वाले प्रभार नियत किये गए।

इस प्रकार, इस मामले को, प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 9 में युक्त अनुबद्धताओं के अनुसरण में 16" व्यास की पाइपलाइन के माध्यम से खाद्य तेलों के प्रहस्तन की अधिकतम दरों के निर्धारण के लिए लिया जाता है। उसके दरमानों में इस प्रशुल्क नियतन को लागू करना केओपीटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। पत्तन के प्रस्ताव को उसके बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

- (iii) केओपीटी ने जुलाई, 2017 में अपना प्रस्ताव दायर किया था। तत्पश्चात्, हमारे द्वारा अतिरिक्त सूचना/ स्पष्टीकरण मांगे जाने पर उत्तर देते समय और संयुक्त सुनवाई के दौरान प्रयोक्ताओं द्वारा किये गए निवेदनों के आधार पर केओपीटी ने अक्टूबर, 2017 के अपने प्रस्ताव में, कुछेक आशोधन किये। अक्टूबर, 2017 के कथित आशोधित प्रस्ताव और संदर्भाधीन मामले के संसाधन के दौरान पत्तन द्वारा प्रस्तुत सूचना/स्पष्टीकरण के साथ, पर इस विश्लेषण में सुविचार किया जा रहा है।
- (iv) प्रशुल्क नीति, 2015 का खंड 9.2, जिसके अंतर्गत केओपीटी के प्रस्ताव पर सुविचार किया जा रहा है, पत्तन को किसी अन्य महापत्तन न्यास में समान सेवा/सुविधा के लिए निर्धारित किया गया प्रशुल्क अंगीकृत करने की अनुमति देता है और इसके अभाव में या निर्धारित दर पर परिकल्पित कार्गो/सेवा/सुविधा का प्रतिनिधि नहीं हो तो पत्तन न्यास 2008 के दिशानिर्देशों के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए इष्टतम क्षमता के हवाले से अथवा दर क्षमता (सेवा/सुविधा/उपस्कर की तकनीकी विशिष्टता के संदर्भ में) के आधार पर पत्तन प्रस्ताव दाखिल कर सकेगा। इस प्रकार, केओपीटी ने तरल बल्क टर्मिनल से संबंधित सामान्यतः 2008 के अप्रकट प्रशुल्क दिशानिर्देशों के प्रतिमानों को अपनाया है।

(v) क्षमता:

अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2008 किसी सुविधा का इष्टतम उपयोग एक वर्ष में 256 दिन अनुबद्ध करते हैं यानी 365 दिन प्रति वर्ष @70% उपयोग। तथापि पत्तन ने बताया है कि तीसरी तेल जेटी विभिन्न प्रकार के तरल कार्गो को प्रहस्त करते हैं, कॉमन प्रयोक्ता पाइपलाइन का प्रयोग केवल खाद्य तेलों के परिवहन के लिए ही किया जा सकता है। इस प्रकार, जुलाई 2017 के अपने अतिरिक्त प्रस्ताव में, पत्तन ने यह माना था कि तीसरी तेल जेटी पर कार्गो प्रहस्तन की वर्तमान प्रवृत्ति के आधार औसतन 1 माह में 9 दिन खाद्य तेल पोतों से आकूपाई रहेगी, परिणामतः एक वर्ष में 108 दिन (यानी 9 दिन X 12 महीने)। बाद में, अक्टूबर, 2017 के अपने संशोधित प्रस्ताव में, केओपीटी ने पीओएल यातायात में प्रक्षेपित वृद्धि और वर्ष 2018 के मध्य से एलपीजी प्रहस्तन के चालू होने के कारण जिसका खाद्य तेल यातायात पर प्रभाव पड़ेगा। 72 दिन की खाद्य तेल पोत आकूपैसी पर सुविचार किया (यानी 6 दिन X 12 महीने)। इस प्रकार पाइपलाइन के एक वर्ष में 72 दिन की अवधि के उपयोग पर सुविचार पर सुविचार किया और 300 टन प्रति घंटा की प्रहस्तन दर के हिसाब से, पत्तन ने पाइपलाइन की क्षमता 518400 टन प्रति वर्ष (यानी 6 दिन X 300 टन प्रति घंटे X 24 घंटे X 12 महीने) निर्धारित की है। पाइपलाइन के उपयोग के बारे में पत्तन के निर्णय के बारे में और 300 टन प्रति घंटा की प्रहस्तन दर पर सुविचार करते हुए अन्य तरल पदार्थों के लिए अपफ्रंट दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित प्रहस्तन दर है, तो पाइपलाइन की क्षमता, पत्तन द्वारा यथानिर्धारित 518400 टन प्रति वर्ष पर विश्लेषण में विश्वास किया जाता है।

(vi) पूंजीगत लागत:

केओपीटी द्वारा यथा-सुविचारित, पाइलपाइन बिछाने की पूंजीगत लागत 598.96 लाख रुपये है। पूंजीगत लागत में, पाइपलाइन, केसिंग, मिट्टी की खुदाई, मिट्टी का भराव, पाइप स्थापन की लागतें तथा अन्य सामग्री लागतें, अनुपंगी पूंजीगत लागतें शामिल हैं। केओपीटी द्वारा यथा सुविचारित पूंजीगत लागत दस्तावेज़ी साक्ष्यों से समर्थित है और उस पर विश्लेषण में सुविचार किया जाता है।

(vii) परिचालन लागत:

(क) पूंजीगत लागत का 2% मरम्मत और अनुरक्षण लागत, पूंजीगत लागत का 1% बीमा लागत और पूंजीगत लागत का 1% अन्य व्ययों का आकलन किया गया है जो तरल बल्क टर्मिनल के अपफ्रंट दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है।

(ख) तरल बल्क टर्मिनल के अपफ्रंट दिशानिर्देशों में निर्धारित मानकों के अनुसार, मूल्यहास, अन्य बातों के साथ-साथ, का परिकलन कंपनी अधिनियम में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार किया जाना होता है। पत्तन द्वारा पूंजीगत लागत का 3.17% की दर से मूल्यहास का आकलन किया गया है। केओपीटी ने पुष्टि की है कि कथित मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों पर आधारित है।

(ग) अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश अनुबद्ध करते हैं कि पत्तन भूमि के पट्टा किराये का आकलन संबंधित महापत्तन न्यास के दरमानों में निर्धारित दरों के आधार पर किया जाना होता है। केओपीटी ने अपने प्रस्ताव में 2306.93 वर्ग मी. जगह पालपलाइन द्वारा घेरे जाने वाले क्षेत्र के लिए मार्ग पर सुविचार किया है। केओपीटी द्वारा सुविचारित लाइसेंस शुल्क भतरी (सीमाशुल्क बद्ध क्षेत्र के भीतर) (अनावृत्त भूमि), नेदी ज़ोन (अनावृत्त भूमि) और रिहायशी ज़ोन के अंतर्गत क्षेत्रों के लिए है।

पत्तन द्वारा प्रस्तुत परिकलन से, यह देखा जाता है कि केओपीटी ने प्रत्येक ज़ोन के लिए ही भिन्न दरों पर सुविचार किया है यानी दरों का एक सैट 11 जनवरी 2016 से 06 अप्रैल, 2016 तक की 3 महीनों के अवधि के लिए है और दूसरा सैट 07 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक की अवधि के लिए है, संभाव्यतः इस आधार पर कि एचडीसी में भूमि का लाइसेंस शुल्क संशोधित किया गया है और कि संशोधित दरें 06 अप्रैल, 2016 से प्रभावी हुई थी। इस बात पर सुविचार करते हुए कि संशोधित लाइसेंस शुल्क 06 अप्रैल 2016 से पहले ही प्रभावी हो चुका है, संशोधन पूर्व दरों पर सुविचार करने का प्रश्न नहीं उठता। इसके अतिरिक्त, इस पर भी विचार करते हुए कि संशोधित लाइसेंस शुल्क पहले ही 06 अप्रैल 2016 से प्रभावी हो चुका है, लाइसेंस शुल्क में अप्रैल, 2017 से 2% प्रति वर्ष की वृद्धि भी लागू हो गई है। इसलिए, विश्लेषण में वर्ष 2017 से संवर्धित लाइसेंस शुल्क को एचडीसी की गोदी भीतर क्वे, गोदी ज़ोन और रिहायशी ज़ोन के लिए विचार में लिया गया है। लाइसेंस शुल्क आकलन में पत्तन द्वारा सुविचार नहीं किया गया है क्योंकि प्रशुल्क परिकलन में करों और उपकरणों को शामिल नहीं किया जाता।

(च) इस प्रकार, उक्त विश्लेषण के आधार पर कुल परिचालन व्यय केओपीटी के आकलन के अनुसार 49.99 लाख रु. के प्रति 49.35 लाख रु. निकलता है।

- (viii) केओपीटी द्वारा यथा-प्रस्तुत प्रहस्तन प्रभारों के परिकलन के लागत विवरण में, उक्त विश्लेषण के अनुरूप, आशोधन कर दिया गया है। आशोधित लागत विवरण की प्रति **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न है।
- (ix) कुल वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) केओपीटी द्वारा यथा-आकलित 145.83 लाख रु. की वार्षिक राजस्व अपेक्षा के प्रति 145.18 लाख रु. निकलती है जो प्रचालन लागत (49.35 लाख रु.) और पूंजीगत लागत (95.83 लाख रु.) का योग है।
- (x) केओपीटी ने संपूर्ण आकलित एआरआर की वसूली पाइपलाइन का प्रयोग कर रहे खाद्य तेल की इष्टतम क्षमता से करने की संकल्पना की है। तदनुसार, 145.18 लाख रु. की आशोधित एआरआर और 5.18 लाख टन की इष्टतम क्षमता को सुविचार में लेते हुए, दर केओपीटी द्वारा यथाप्रस्तावित 28.13 रु. प्रति टन के स्थान पर 28.00 रु. प्रति टन निकलती है।
- (xi) 28.00 रु. प्रति टन की दर, केओपीटी द्वारा यथाप्रस्तावित, 16" व्यास की 5.70 कि.मी. लंबी खाद्य तेल पाइपलाइन के लिए है, केओपीटी ने अपने प्रस्ताव में 16" व्यास की पाइपलाइन को छोड़कर कॉमन प्रयोग आधार पर खाद्य तेलों के प्रहस्तन के लिए 4.95 रु. प्रति एमटी के उपयोग प्रभार लागू करने का भी (28.00 रु. प्रति टन/ 5.70 कि.मी.) प्रस्ताव किया है पत्तन की यह राय है कि पाइपलाइन का व्यास 16" से कम होने के मामले में, पूंजीगत लागत के कम हो जाने की भी प्रत्याशा है और कि, इसके साथ ही, प्रवाह दर भी गिर जायेगी जबकि वहां लागत प्रति टन प्रति कि.मी वही रहने की संभावना है।
- केओपीटी द्वारा किया गया निवेदन किसी गणना से समर्थित नहीं है। पाइपलाइन के व्यास में परिवर्तन की प्रमात्रा का पूंजीगत लागत और फ्लो रेट में परिवर्तन की प्रमात्रा के सीधे अनुपातिक होना जरूरी नहीं है। अतः यह प्राधिकरण पत्तन द्वारा प्रस्तावित कथित प्रभार को अनुमोदित करने की स्थिति में नहीं है। तथापि, केओपीटी को सलाह दी जाती है कि वह 16" व्यास की पाइपलाइनों से भिन्न पाइपलाइनों के उपयोग के लिए प्रभारों के नियतन का एक उपयुक्त प्रस्ताव, सुविधा के चालू होने से पहले लेकर आये।
- (xii). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार करते समय, केओपीटी ने स्फीति को कवर करने के लिए डब्ल्यूपीआई 60% सीमा तक आधार प्रशुल्क के सूचकांकन का प्रस्ताव भी किया है। केओपीटी का संपूर्ण दरमान, अनुमोदित दरों सहित, अब एक वर्ष पश्चात् मान लो 31 मार्च 2019, समीक्षा के लिए अपेक्षित है। यह ध्यान देने योग्य है कि केओपीटी ने प्रशुल्क के अनुमोदन का प्रस्ताव एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च, 2019 तक के लिए ही किया है। सूचकांकन के इस पहलू की उस समय की स्थिति के अनुसार उस समय समीक्षा की जा सकती है। निष्पादन मानक 300 टन प्रति घंटे पर निर्धारित किया जाता है, जैसा केओपीटी ने प्रस्तावित किया है।
- (xiii). इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश आम तौर पर राजपत्र अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् उत्तरव्यापी प्रभाव से प्रभावी होते हैं। चूंकि प्रशुल्क व्यवस्था पहले से चल रही है, 15 दिनों की अग्रणी अवधि पर्याप्त पाई गई है। तदनुसार, पाइपलाइन प्रयोग प्रभार भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 15 दिन का समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होंगे। इसके अतिरिक्त, पाइपलाइन प्रयोग के प्रशुल्क को केओपीटी द्वारा केओपीटी के वर्तमान दरमानों में भाग IX अधिकृत सेवा प्रदाताओं के लिए प्रभार के खंड 4 में अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव है। अतः अब अनुमोदित किये जा रहे पाइपलाइन प्रयोग प्रभारों की वैधता केओपीटी के वर्तमान दरमानों की वैधता के साथ सह-समाप्य है, जैसा पत्तन ने प्रस्ताव किया है।

10.1 परिणाम में और ऊपर दिये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर केओपीटी के वर्तमान में भाग- IX के अंतर्गत- अधिकृत सेवा प्रदाताओं के लिए प्रभार के खंड- 4 के रूप में निम्नलिखित उपबंध अंतर्विष्ट करने का अनुमोदन किया जाता है:-

" खंड - 4: केओपीटी के हल्दिया गोदी परिसर (एचडीपी) में हल्दिया तेल जेटी (एचओजे)-III से फिंगर जेटी के बीच 16" व्यास पाइपलाइन के प्रयोग प्रभार:-

- (i) 'खाद्य तेल' की परिभाषा। 'खाद्य तेल' का अर्थ पीएलएमओसी, एसबीओ, सोया तेल आदि (कच्चा और परिष्कृत दोनों ही) हैं।
- (ii) तीसरी तेल जेट से फिंगर जेटी को 16" व्यास की कॉमन प्रयोक्ता के खाद्य तेल पाइपलाइन के माध्यम से खाद्य तेल 'प्रहस्तन प्रभार':

क्र.सं.	वस्तु	दर रु. में प्रति एमटी
1.	पाइपलाइन प्रयोग प्रभार	28.00

- (iii) खाद्य तेल प्रहस्तन के लिए निष्पादन मानक 300 टन प्रति घंटा है।"

10.2. केओपीटी को दरमानों में उक्त उपबंधों को उपयुक्त रूप से अंतर्विष्ट करने की सलाह दी जाती है।

10.3. उक्त प्रभार पाइपलाइन प्रयोग प्रभार भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 15 दिन का समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होंगे और उनकी वैधता केओपीटी के वर्तमान दरमानों की वैधता के साथ सह-समाप्य है, अर्थात् 31 मार्च 2019 तक। तत्पश्चात् दिया गया अनुमोदन स्वतः व्यपगत हो जायेगा जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से विस्तार नहीं कर दिया जाता।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./314/17]

अनुलग्नक

हल्दिया गोदी परिसर कोलकाता पत्तन न्यास की एचओसी-III से फिंगर जेटी तक 16" व्यास की कॉमन प्रयोक्ता पाइपलाईन डालने से खाद्य तेलों के प्रहस्तन के लिए प्रशुल्क का परिकलन

क्र.सं.	विवरण	केओपीटी के जुलाई 2017 के आरंभिक प्रस्ताव के अनुसार	केओपीटी के सितंबर 2017 के संशोधित प्रस्ताव अनुसार	केओपीटी के अक्तूबर 2017 के संशोधित प्रस्ताव अनुसार	प्राधिकरण के आशोधनों के अनुसार
		₹.	₹.	₹.	₹.
1	इष्टतम क्षमता प्रति वर्ष (एमटी में)	777600	777600	518400	518400
2	पूँजीगत लागत	59896245.00	59896245.00	59896245.00	59896245.00
3	खाद्य तेल पोत का ओसत पार्सल आकार	8700	8700	8700	8700
4	खाद्य तेल पोत की अनुमानित संख्या प्रति वर्ष	89	89	60	60
5	परिचालन लागत				
	क) पाइपलाइन की मरम्मत और अनुरक्षण (पूँजीगत लागत का 2%)	1197924.90	1197924.90	1197924.90	1197924.90
	ख) बीमा (पूँजीगत लागत का 1%)	598962.45	598962.45	598962.45	598962.45
	ग) मूल्यह्रास (पूँजीगत लागत का 3.17%)	1898710.97	1898710.97	1898710.967	1898710.967
	घ) मार्गाधिकार अनुमति प्रभार (टिप्पणी-1)	704718.00	704718.00	704718	640389
	ड) अन्य व्यय (पूँजीगत लागत का 1%)	598962.45	598962.45	598962.45	598962.45
	च) ईंधन लागत (प्रति पोत 120 लीटर x 57.23 प्रति लीटर)	611216.40	-	-	-
	योग (5)	5610495.17	4999278.77	4999278.77	4934949.97
6	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) (पूँजीगत लागत का 16%)	9583399.20	9583399.20	9583399.20	9583399.20

7	वार्षिक राजस्व प्रतिफल [5 + 6]	15193894.37	14582677.97	14582677.97	14518349.17
	क) पाइपलाईन द्वारा कार्गो प्रहस्तन प्रभार (95%)	14434199.65	-	-	-
	ख) विविध प्रभार (5%)	759694.72	-	-	-
8	पाइपलाईन प्रभार प्रति मीट्रिक टन	18.56	18.75	28.13	28.00
9	एचडीसी में डली अन्य खाद्य तेल पाइपलाईनों के लिए पाइपलाईन प्रभार	-	3.30	4.95	-
10	विविध प्रभार (प्रति पोत पिंगिंग)	8535.90	-	-	-

टिप्पणी 1:

जोन	संबंधित जोनों में पाइपलाईन कवरेज क्षेत्र (वर्ग मीटर)	केओपीटी किराया अनुसूची के अनुसार 2017 में लागू दर (प्रति 100 वर्ग मीटर प्रति माह रुपए में)	मार्गाधिकार अनुमति शुल्क (रुपए में)
गोदी की भीतरी जोन	1548.93	2680.56	498240
गोदी जोन	375.96	1488.18	67140
रिहायशी जोन	382.06	1636.08	75010
			640389

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st November, 2017

No. TAMP/58/2017-KOPT.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Kolkata Port Trust for fixation of tariff for handling of edible oil from vessels berthed at 3rd oil jetty to Finger Jetty of Haldia Dock Complex through 16" dia Pipeline on a common user basis, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/58/2017-KOPT

Kolkata Port Trust

Applicant

QUORUM:

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER(Passed on this 14th day of November 2017)

This case relates to the proposal received from Kolkata Port Trust (KOPT) for fixation of tariff for handling of edible oil from vessels berthed at 3rd oil jetty to Finger Jetty of Haldia Dock Complex (HDC) through 16" dia Pipeline on a common user basis.

2.1. The main points made by KOPT in its proposal dated 10 July 2017 are summarised below:

- (i). The Land Policy Guidelines issued by the Ministry of Shipping (MOS) provides that the common user pipeline laid by one party shall be used by other parties on such terms and conditions as agreed between the parties and the Port Trust Board.

- (ii). M/s Emami Agrotech Ltd (EAL) have laid one 16' dia Edible oil pipeline from Haldia Oil Jetty (HOJ) - III to finger jetty of HDC, KOPT, as approved by the Board of KOPT. [The copy of the Board Resolution approving way leave permission for laying of one no. 16' dia pipeline from HOJ-III to finger jetty is furnished by KOPT.]
- (iii). In pursuance of the provision of the Land Policy Guidelines, most of the importers and storage operators of edible oil have agreed to use the 16' dia edible oil pipeline laid by M/s EAL at 3rd oil jetty. They have also agreed to the terms and conditions for using the said pipeline at the payment of ₹. 40/- per ton to M/s EAL.
- (iv). The Board of Trustees vide Resolution No. R/39/HDC/ADMN/1/07/ 2016 dated 1 July 2016 has approved the terms and conditions in this regard. [The copy of the Board Resolution approving terms and conditions is furnished by KOPT.]
- (v). Further, the Land Policy Guidelines provides the scope for deciding the terms and conditions towards usage of a pipeline laid by one party by other with the consent of Board. The rate and other conditions of usage of such pipeline facilities should be approved by TAMP as the pipeline facilities from the jetties are used for cargo handling purpose and the same is approved by the Board vide its Resolution no. R/283/HDC/ADMN/3/5/2017 dated 31.05.2017. [The copy of the Board Resolution approved on 31 May 2017 is furnished by KOPT.]

2.2. The highlights of the proposal are as follows:

- (i). The KOPT handles different types of liquid cargo inside the impounded dock of HDC. In the year 2016-17, the KOPT has handled 3.96 million tonnes of liquid cargo inside the impounded dock of HDC by 486 vessels.
- (ii). There has been an increase in the capacity for handling dry bulk cargo inside the impounded dock of HDC by 6 million tonnes in the recent past with deployment of Mobile Harbour Cranes at berth no. 2, 8 and 13. In order to utilize the added capacity of 6 million tonnes of dry bulk cargo, there is a need to increase handling of dry bulk cargo vessels inside the impounded dock which is restricted now due to the constraints of the lock gate. Therefore, the KOPT decided to handle edible oil vessels outside the impounded dock to make room for handling additional dry bulk cargo vessels inside the impounded dock.
- (iii). In view of the above, permission was granted to M/s EAL to lay one common user 16" dia edible oil pipeline from 3rd oil jetty upto finger jetty. M/s EAL have already laid the pipeline upto finger jetty. M/s EAL as well as the other importers of edible oil have connected their individual edible oil pipelines with the said 16" dia common user edible oil pipelines at finger jetty through flexible hoses. The Land Policy Guidelines stipulates that the rate and other conditions of usage of such pipeline facilities should be approved by TAMP as the pipeline facilities from the jetties are used for cargo handling purpose.
- (iv). In absence of any other Reference tariff for the instant case, the proposal is filed under 2008 guidelines which is the only guideline available for assessment of tariff.
- (v). As per the guidelines, the optimal capacity is to be assessed on the basis of actual operation for 255 days in a year. However, the 3rd oil jetty handles different types of liquid cargo viz. Crude, Naptha, POL Products and Edible Oil. In future, LPG is also going to be handled at this jetty. As the common user pipeline laid by M/s EAL will be utilized only for transportation of edible oil, as no other commodity other than edible oil can be transmitted through this pipelines, it is presumed that jetty will be occupied by edible oil vessels on an average of 9 days a month. Thus, assessment of the optimal capacity has been carried out based on 108 days in a year, as per the parameters given below:

No of days the pipelines will be used for handling edible oil at 3 rd oil jetty	108 days
Discharge rate is as per TAMP Guidelines.	300 tonnes per hour
Optimal Capacity assessed = 108 days * 300 tonnes per hour* 24 hour	777600 tonnes

- (vi). The number of vessel estimated on the basis of average parcel load of edible oil vessels handled at HDC during 2016-17 i.e. 8700 tonnes and optimal pipelines capacity of 777600 tonnes.

Optimal Capacity assessed	777600 tonnes
Average parcel load of edible oil vessels handled at HDC during 2016-17	8700 tonnes
Edible oil vessels (777600/8700)	89

(vii). Capital Cost Estimation:

The cost break up sent by M/s EAL duly certified by Chartered Engineer on 30 May 2017 is as follows:

Sr. no.	Description	Amount (in ₹.)
1.	16 inch API 5L Pipe	22213170
2.	20 inch ERW C class Pipe for casing	556920
3.	24 inch ERW C class Pipe for casing	485100
4.	16 inch Seamless Long Bend	308700
5.	16 inch Seamless Short Bend	81900
6.	16 inch Gate Value, Class 150, Flange End	204750
7.	12 inch Gate Value, Class 150, Flange End	173250
8.	8 inch Gate Value, Class 150, Flange End	29400
9.	16 inch MS flange, Class 150, SORE	7560
10.	12 inch MS flange, Class 150, SORE	8508
11.	8 inch MS flange, Class 150, SORE	2310
12.	Wrapping Coating Bitumin Tape	1965600
	Total Material Cost (A)	26037168
1	Earth excavation	1791400
2	Earth excavation (Hard Stand by manual cutting)	416000
3	Earth filing	411750
4	Road crossing by horizontal boring (below 20 meter)	550000
	20 meter to 30 meter	780000
	above 30 meter	1500000
5	Pipe erection	10752000
6	Pipe joint	1570400
7	Online item i.e. Values	17600
8	Wrapping Coating	1936000
9	Materail Unloading	174000
10	Survey Cost	250000
11	Cathodic Protection	2500000
	Total Service Cost before Service Tax	22649150
	Add Service Tax @ 15%	3397373
	Total Service Cost after Service Tax (B)	26046523

	Total Cost for pipe laying (A)+(B) = (C)	52083691
	One time Supervision Cost @ 15% of (C)	7812554
	Total Project cost	59896245

(viii). Estimation of Operating Cost is as per norms prescribed in 2008 Guidelines

Item of cost	Basis adopted	Amount in ₹.
Repairs & Maintenance of Pipelines	2% of capital cost as per TAMP guidelines (59896245*2%)	1197924.90
Insurance	1% of capital cost as per TAMP guidelines (59896245*1%)	598962.45
Depreciation	3.17% of capital cost as per TAMP guidelines (59896245*3.17%)	1898710.97
Other Expenses	1% of capital cost as per TAMP	598962.45
Way leave fees	As per the current SOR and the land for which way leave permission granted	704718.00
Fuel cost per vessel (for operating pig launcher)	120 liters per vessel as per estimation given by M/s Emami (120 ltrs*89 vessels@57.23 per ltr. estimated by Emami)	611216.40
	Total O&M cost	5610495.17

(ix). Total Revenue Requirement and apportionment of total Revenue Requirement

Item	Amount in ₹.
Total O&M Cost	5610495.17
ROCE (16% of Capital Cost)	9583399.20
Total Revenue Requirement	15193894.37
Cargo Handling Charges through pipeline (95%)	14434199.65
Miscellaneous charges (5%)	759694.72

(x). Based on the above working, the KOPT has arrived at the proposed rates as follows:

Items	Basis of Assessment	Amount
Cargo Handling Charges through pipeline (95%)	₹.14434199.65/777600 tons	₹.18.56 per ton
Miscellaneous charges (5%)	₹. 759694.72/89 vessels	₹.8536/- per vessel

2.3. As the proposed rate of ₹. 18.56/- per ton has been assessed for an edible oil pipeline of length of 5682.15 meters in the instant case, the rate which other users may charge for similar pipeline at other berths is proposed at ₹ 3.26/- per ton per km (₹ 18.56/5.682 kms) towards Cargo Handling Charges. The miscellaneous charges per vessel will remain same at ₹ 8536/- per vessel.

2.4. It is seen that the KOPT Board has approved the charges for handling of Edible oil through common user pipeline from 3rd oil jetty to finger jetty at ₹. 18.52 per Metric Tonne and the Miscellaneous charges at ₹. 8519 per vessel and charges for handling edible oil through common users from different berth at ₹ 3.25 per metric Tonne per kilometer. In this context, the KOPT has stated that to arrive at the proposed rates for handling of edible oil, the revised rates of fuel and way leave permission fees have been considered and that the revised proposed rates will be placed before the Board in the next Board meeting for information.

2.5. Thus, the proposal of KOPT seeks approval for the following:

- “(i). The definition of “Edible oil”. “Edible oil” means PLMOC, SBO, SOYA OIL etc. (both crude and refined).
- (ii). Charges for handling of edible oil through common user 16’ dia edible oil pipelines from 3rd oil jetty to finger jetty:

Sr.no.	Commodity	Unit	Rate in ₹.
1.	Handling charges for Edible oil pipelines usage	Per Metric Tonne	18.56
2.	Miscellaneous charges (pigging etc.)	Per vessel	8536

- (iii). Charges for handling of edible oils through common user edible oil pipelines from the different berths at HDC (other than through 16’ dia edible oil pipelines from 3rd oil jetty to finger jetty):

Sr.no.	Commodity	Unit	Rate in ₹.
1.	Handling charges for Edible oil pipelines usage	Per Metric Tonne per kilometer	3.26
2.	Miscellaneous charges (pigging etc.)	Per vessel	8536

General Note:

The tariff will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 April 2014 and 1 January of every succeeding year. Such automatic adjustment of Tariff will be made every year and the adjusted tariff cap will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.”

3. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the KOPT proposal dated 10 July 2017 was forwarded to the concerned users/ user organisations (as per the list forwarded by KOPT) vide our letter dated 13 July 2017, seeking their comments. Only one of the users viz., EAL has furnished its comments vide its e-mail dated 25 July 2017 stating that the EAL does not agree to the proposal as the proposed tariff is not viable to them. Similar comments have been furnished by the EAL subsequent to the joint hearing. The KOPT has responded to the said comments of EAL.

4.1. A joint hearing on the case in reference was held on 31 August 2017 at the KOPT premises in Kolkata. At the joint hearing, the KOPT made a brief power point presentation of its proposal. The KOPT and the users/ user organisations have made their submissions.

4.2. As decided at the joint hearing, some of the users/ user organisations have furnished their comments. The said comments were forwarded to the KOPT as feedback information. The KOPT has responded vide its letter dated 8 September 2017.

5. Based on a scrutiny of the KOPT proposal, additional information/ clarification were sought from KOPT vide our letter dated 4 August 2017. The KOPT has responded vide its letter dated 8 September 2017. The information/ clarification sought by us and the response of KOPT thereon are tabulated below:

Sl. No.	Information/ clarification sought by us	KOPT's Reply
A.	General	
(i).	The KOPT has stated that the revised proposed rates will be placed before the next Board meeting. As already requested vide our letter of even number dated 13 July 2017, the KOPT to furnish a	Copy of Board Reso. No. R/331/HDC/ADMN/3/8/2017 dated 17 August 2017 is furnished by KOPT.

	copy of the Board resolution approving the rates as proposed by KOPT.	
(ii).	We have under cover of our letter of even number dated 26 July 2017 forwarded the copy of the comments received from Emami Agrotech Limited (EAL) and requested KOPT to furnish its comments on the submissions made by EAL. The KOPT to furnish its comments.	The KOPT submitted during the hearing that it would be possible to handle 0.78 million tonnes of edible oil per annum going by the present utilization pattern of the 3 rd oil jetty as a while. For this, the rate for the pipeline utilization charge should be reasonable. The users have been finding the current of ₹. 40/- per ton is not encouraging for greater utilization of 3 rd oil jetty for handling edible oil. Therefore, the proposed charge of ₹. 18.56 may encourage the users to use the 3 rd oil jetty more. KOPT also mentioned that the proposed rate may be introduced for 1 year subject to the condition that the same may be reviewed by TAMP within this period based on the actual utilization of the 3 rd oil jetty by the different users for handling edible oil.
(iii).	The KOPT in its proposal has stated that the importers and the storage operators of edible oil have agreed to use the 16" dia edible oil pipeline laid by EAL by making a payment of ₹.40/- per tonne to EAL for utilization of the pipeline. In this connection, the proposal of the port now seeking approval for a rate of ₹.18.56 per tonne towards cargo handling charges for Edible oil pipeline usage, is not clear. KOPT to clarify the nature of both the levies referred above.	<p>M/s EAL have laid one 16" dia edible oil pipeline from HOJ-III to Finger jetty of HDC.</p> <p>The Land Policy Guidelines issued by the MOS provides that as far as possible, the pipelines may be laid on common user basis. If any other party wants to use the pipelines, they may be given permission in such terms as agreed to between the parties and the Port Trust Board.</p> <p>In keeping with the above provision of LP Guidelines, KOPT had a meeting with all the prospective users and EAL on 14.06.2016 and 15.06.2016 where it was agreed that all the users would pay ₹. 40/- per ton to EAL for using their edible oil at 3rd oil jetty. This was also agreed to by KOPT Board and the same was introduced for a period upto June 2018. The copy of the minutes of the Board Resolution dated 01.07.2016 is furnished by the Port.</p> <p>Subsequently, the users of the pipelines facilities of EAL at HOJ-III started requesting for lowering the rate of ₹. 40/- per tone agreed upon by them earlier.</p> <p>KOPT also noted that although Land Policy provided for deciding on the terms and conditions of usage of a pipelines laid by one party by other with the consent of Board, however, as the pipelines facilities from the jetties are for cargo handling purpose and as such, the rate and other conditions for usage of such cargo handling facilities should be approved by TAMP.</p> <p>In keeping with the above KOPT has internally calculated the tariff/charges leviable for common use of the edible oil pipeline laid from HOJ-III to finger jetty of HDC on the basis of relevant guidelines of TAMP. This rate has been calculated as 18.56 per ton and same has been approved by the Board.</p>
(iv).	The KOPT to certify that no further improvement due to technical reasons would be possible in the dimensions of the pipeline considered, which may have an impact on pumping rate/ capacity/ handling rate.	Confirmed as the concerned 16" dia (underground) edible oil pipelines has already been laid in June 2016 and is operational since then. The proposed rates are for handling edible oils through these 16" dia pipelines.
(v).	The KOPT to confirm whether the number of vessels calculated at 89 per annum in the proposal is inclusive of vessels destined to EAL also.	Confirmed.

(vi).	The KOPT has allowed EAL to lay pipelines other than 16" dia pipeline also. The KOPT to intimate tariff arrangement in respect of cargo handled through those pipelines of other users, apart from EAL.	<p>Other pipelines for which way leave permission have been granted to EAL are of diameter 10" and 12". All these pipelines have been laid from different berths inside the impounded dock where other users are also having their own edible oil pipeline. Therefore, no requirement for common use of those 10" / 12" pipelines of EAL inside the impounded dock has been faced / proposed till now.</p> <p>As there is only one edible oil pipeline from 3rd oil jetty laid by EAL, tariff arrangement has been proposed for common usage of the same by other users.</p> <p>However, in the tariff proposal under consideration, KOPT has also proposed for a single rate on per km per ton basis which may be used for other edible oil pipelines laid by different parties depending upon the length of common usage.</p>
B.	<p>Optimal Capacity:</p> <p>The optimal capacity of the pipeline has been worked out by KOPT by considering 108 days of utilization in a year. This is reportedly based on the present trend of arrival of edible oil vessels. If the trend of arrival of vessel changes, the tariff may have to be reviewed.</p>	<p>It is agreed that in the event of handling higher volume of other liquid cargo at 3rd oil jelly which are having higher priority than edible oil vessels, the extent of handling of edible oil at 3rd oil jelly may come down in future.</p> <p>In keeping with the above, KOPT suggested during the hearing that the tariff may be fixed for one year at the present on the basis of 0.78 Million tonnes of annual cargo proposed by KOPT in the tariff proposal. According to KOPT, it is possible to handle 0.78 million tonnes of edible oil in a year on the basis of the current trend of cargo handling at 3rd oil jetty provided the utilization charges of the pipelines laid by EAL is attractive to the trade. The tariff as proposed may be reviewed on the basis of the trend of edible oil handling during the period of one year and if required, TAMP may consider to re-fix the tariff subsequently taking into account the surplus / deficit of the previous period.</p>
C.	Capital cost:	
(i).	The documentary evidence furnished by KOPT in support of the capital cost is of May 2017. The KOPT to examine whether the capital cost will remain the same in the GST regime also.	<p>The pipelines concerned has been laid by EAL prior to commencement of the GST regime.</p> <p>Service Tax element at the rate of 15% has been included under capital cost calculations as submitted by EAL certified by Chartered Accountant Firm in 2017.</p>
(ii).	The total project cost of laying pipelines of ₹. 598.96 lakhs includes one-time supervision cost at 15% of the total cost of ₹. 520.83 lakhs. Presumably, this one time supervision cost is payable by the EAL to KOPT as per the Land Policy Guidelines. The KOPT to examine whether inclusion of one time supervision charge in capital cost for the purpose of allowing return is in order.	The one time supervision charge is paid for supervising the pipeline laying activities as per the Land Policy Guidelines. As such, KOPT has considered the same within the project cost.
(iii).	The KOPT to note that though fuel cost for operation of Pig launcher has been taken into account, the capital cost of Pig Launcher does not appear to have been included in the Project Cost.	<p>Considering pigging to be done by the respective users of the pipelines as indicated by the users during hearing, the tariff for utilization charge has been re-assessed by excluding the fuel cost for pigging and loading 100% cost for pipelines utilization charge without keeping any provision for miscellaneous charge in absence of pigging etc.</p> <p>The re-assessed tariff comes to ₹. 18.75/- per ton. The</p>

		KOPT has furnished the calculation. The element of “miscellaneous charges” of ₹ 8536/- per vessel earlier proposed towards pigging arrangement is now proposed to be withdrawn.
D.	Operating cost:	
(i).	The KOPT to confirm whether the depreciation of 3.17% considered on the cost of pipelines is based on the provisions of the Companies Act, 2013.	Confirmed.
(ii).	KOPT to furnish detailed working in respect of calculation of license fee for way leave permission by indicating the area as well as the way leave fees. Reference to the Rent Schedule considered also to be indicated.	The calculations are furnished by KOPT.
(iii).	a) The KOPT to clarify how the cost of operating the pig launcher would be relevant in the estimation of operating cost. b) The basis for considering the fuel consumption towards operating of pig launcher at 120 litres per vessel to be supported by documentary evidence. c) Furnish documentary evidence in support of cost of the fuel considered in the calculation.	Element of pigging cost has been removed and the tariff has been proposed afresh. The same has come to be ₹ 18.75 per ton. The calculation sheet is furnished by KOPT.
E.	Calculation of Handling charge/ Miscellaneous charge:	
	The reason for prescribing the Miscellaneous Charges on ‘per vessel’ basis instead of ‘per tonne’ basis to be justified.	Same as above.
F.	Scale of Rates:	
(i).	The proposal of the KOPT is to enable levy charges for the use of 16” dia edible oil pipeline laid by EAL. The same handling charge has been taken as base and a rate has been prescribed for handling of edible oils other than through 16” dia pipeline. The KOPT to clarify whether the proposed rate of ₹3.26 per MT will hold good if the diameter of pipeline is different than 16” dia pipeline.	The proposed tariff for the 16” dia edible oil common user pipelines laid from HOJ-III to finger jetty has been considered to be taken as the basis for arriving at the rate for common use of edible oil pipelines laid by various users at the other different jetties of HDC. In case of pipeline of diameter lower than 16”, the capital cost is expected to come down. At the same time, the flow rate considered of 16” pipelines is also expected to come down and thereby the cost per ton per km is expected to remain same. On this assumption, the rate of ₹ 3.26/- per ton per km (reworked to ₹ 3.30 per ton per km) has been proposed commonly for common usage of all edible oil pipelines irrespective of diameter.
(ii).	The services envisaged to be rendered under the ‘Handling charges’ and the ‘Miscellaneous charges’ to be listed out and indicated separately under each head of charges.	Considering that pigging, etc. are done by the respective users, the SOR is reworked. It is now proposed to fix tariff as “Pipeline Usage Charge” instead of “Handling Charge”. No “Miscellaneous Charge” is proposed on the basis of the submission given by the users during the hearing. Accordingly, the provision proposed to be incorporated under Part-IX (charges for authorized service providers) in the KOPT Scale of rates notified vide Gazette no. 457 dated 13.12.2016 is also revised as follows: “Section 4: Tariff for handling edible oils through common user pipelines from different berths/ jetties of

		<p>HDC.</p> <p>(i). The definition of 'Edible Oil', "Edible Oil" means PLMOC, SBO, SOYA OIL etc. (both crude and refined).</p> <p>(ii). Pipelines usage charge for handling of Edible oils through common user 16" dia edible oil pipeline from 3' oil jetty to finger jetty ₹ 18.75/- per Metric Tonne.</p> <p>(iii). Pipelines Usage Charges for handling Edible Oils through common users edible oil pipelines from different berths at HDC (other than through 16" dia edible oil pipelines from 3rd oil jetty to finger jetty): ₹ 3.30/- per Metric Tonne per Kilometre or part thereof.</p>
(iii).	In the General Note proposed by the Port, the reason for considering the year 2014 as base for application of 60% indexation to be clarified, considering that the capital cost and operating cost estimates have been considered based on the rates prevailing in the year 2017.	<p>The year 2014 was mentioned inadvertently.</p> <p>The indexation clause may be modified as below:</p> <p>"The tariff caps will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2017 and 1 January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year."</p>
(iv).	For the purpose of indexation, the KOPT to propose Performance Standards.	Since the tariff is being proposed for common usage of the pipelines which is independent of the pumping rates etc. no Performance Standard has been proposed. The WPI based indexation has been proposed to take care of the fluctuation in the various costs to be incurred in maintenance etc.

6. While furnishing the additional information/ clarification vide its letter dated 8 September 2017, the KOPT is seen to have reviewed its proposal. The revision is to the limited extent of excluding the operating cost towards Fuel cost per vessel (for operating pig launcher), which was considered by the KOPT in its initial proposal. Further, as against the segregation of the annual revenue requirement (ARR) into handling (95%) and miscellaneous (5%) as proposed by the KOPT in its initial proposal, the KOPT has now proposed to recover 100% ARR from handling charges, without keeping any provision for miscellaneous charge in the absence of pigging etc. In view of the said review, the tariff initially proposed by the KOPT at ₹ 18.56 per MT has now been reworked by the port at ₹ 18.75 per MT.

7.1. On scrutiny of the response of the KOPT furnished vide its letter dated 8 September 2017 and the comments of KOPT on the submissions made by EAL, some gaps were observed in the information furnished by KOPT. Accordingly, we have vide our letter dated 28 September 2017 sought some information/ clarification from KOPT. The KOPT has responded vide its letter dated 27 October 2017. The information/ clarification sought by us and the response of KOPT thereon are tabulated below:

Sl. No.	Clarification sought by us	KOPT Reply
(i).	The copy of the Board resolution approving the rates proposed by KOPT, reported to have been attached by KOPT, is not found attached alongwith the KOPT letter. The same to be furnished.	Copy of the Board approval No. R/33/HDC/ADMN/3/8/2017 dated 17.08.2017 is furnished by KOPT for continuing the handling rate of ₹ 40 per MT till new rate is approved and notified by TAMP.
(ii).	With regard to the rate of ₹ 40/- per MT, the KOPT has stated that in a meeting held by KOPT with prospective users and Emami Agrotech Limited (EAL) on 14 and 15 June 2016, it was agreed that all users would pay ₹ 40/- per MT to EAL for using their pipeline for handling edible oil. The KOPT has also stated that the same was agreed by the KOPT Board and the same was introduced for a period upto June 2018. In this connection, the	

	following information is required from KOPT:	
(a).	Basis/ Cost details/ Workings to arrive at the rate of ₹.40/- per MT.	It may be seen from the minutes for the meeting amongst the users, Emami Agrotech Ltd. (Service Provider) & KOPT held on 14.06.2016 & 15.06.2017 that the rate of ₹.40 per ton arrived after detailed discussions. Incidentally, the said rate of ₹. 40/- per ton was suggested by M/s Emami Agrotech Ltd. & was accepted by the different users after detailed discussions.
(b).	Considering that the users of the facility had agreed initially in June 2016 to pay an amount of ₹.40/- per MT to EAL for handling of Edible oil, as per the Minutes of the meeting furnished by KOPT, the reason for them to now oppose the said levy of ₹.40/- per MT during the joint hearing is not clear. The reason for their request to lower the rate may be intimated.	The users of the said common user pipelines have indicated during the hearing taken by TAMP that at the relevant point in time in 2015, they had agreed to the said rate of ₹.40/- per MT, although the same was higher side, to tide over the high incidents of demurrage arising out of significant pre berthing detention periods (PBD) at HDC and that the said rate is for a temporary period of only 2 years within which the same would be reviewed. The premier users has also expressed about the high cost of handling edible oil at 3rd Oil jetty.
(c).	Based on the approval of the KOPT Board, the KOPT has already introduced the rate of ₹.40/- per MT for a period of 2 years from June 2016 upto June 2018. In the event, if the rate of ₹ 18.75 per MT as proposed by the port is approved, the validity period for the proposed rate of ₹18.75 per MT may be intimated.	The tariff for pipeline usage has been proposed to be incorporated in the existing Scale of Rates under Section 4 of Part IX (Charges for authorized service providers (in KOPT's Scale of Rates notified vide Gazette no. 457 dated 13.12.2016. As such, the proposed rates of pipelines usage will be valid till validity of KOPT existing Scale of Rates.
(d).	The KOPT has not proposed Performance Standards on the ground that the tariff is being proposed for common usage of the pipelines which is independent of the pumping rates etc. and that the WPI based indexation has been proposed to take care of the fluctuation in the various costs to be incurred in maintenance etc. In this connection, reference is drawn to Clause 9.1 and 9.3 of the Tariff Policy, 2015, which requires the port to propose performance standards to be achieved by the service provider and that the indexation in tariff is subject to achievement of Performance Standards committed by Major Port Trusts and if a particular port does not fulfil the Performance Standard, no indexation would be allowed during the next year. Thus, the KOPT is requested to note that in the event of non-prescription of Performance Standards, the tariff will not undergo any change, and would remain static, till it is completely reviewed on the next occasion. In such a scenario, the general note on WPI indexation, as proposed by the Port in its draft Scale of Rates may also not be relevant.	The performance standard for edible oil averaging over CPO/RDB Palm Oil/ CDSO/ Sunflower Oil may be kept at 300 MT per hour. This is in line with performance standard prescribed in the Tariff Guidelines.
(e).	The detailed working in respect of calculation of license fee for way leave permission by indicating the area as well as the way leave fees and the Reference to the Rent Schedule, reported to have been enclosed by the Port is not found along with the KOPT letter. The same may be furnished.	The statement showing the calculation of way-leave permission fees in respect of 16' dia edible oil pipeline laid from 3 rd Oil jetty to Finger Jetty is furnished by KOPT.
(iii).	Further, the comments furnished by EAL vide its letter dated 04 September 2017 was	The letter dated 04.09.2017 of EAL has been examined. They have specifically mentioned that the maximum edible

	<p>forwarded to KOPT for its comments vide our letter of even number dated 06 September 2017. The KOPT is not seen to have furnished its comments on the submissions made by EAL more particularly with regard to submissions made by EAL on the maximum quantity of edible oil to be handled at HOJ-III at 4 lakh tonnes per annum and the rate of ₹39.64 per MT as suggested by EAL, which is supported by workings given by EAL.</p>	<p>oil capacity at HOJ-III, may be at best utilized for 6 days for handling edible oil in a month considering the projected increase in POL traffic and commencement of LPG handling from middle of 2018. In that scenario, the optimum capacity of 3rd oil jetty for handling edible oil will be 0.5184 million tones (72 days in a year x 300 MT per tons x 24 hours). In that scenario, the tariff will become ₹ 28.13 per ton, as shown below:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl. no.</th><th>Particulars</th><th>Amount in ₹</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Optimal Cargo traffic per annum in MT through this pipeline (6 days x 300 tonnes x 24 hours x 12 months)</td><td>518400</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Capital Cost of 5.7 km pipeline laying as given by EAL</td><td>5,98,96,245.00</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Average parcel size of Edible oil Vessel in MT (2016-17 edible oil parcel size at HDC)</td><td>8700</td></tr> <tr> <td></td><td>Total no. of Edible oil Vessel per annum (777600 / 8700=89.38 i.e. 89)</td><td>89</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Operating Cost</td><td></td></tr> <tr> <td>a</td><td>Repairs & Maintenance of Pipelines @ 2% of capital cost</td><td>1197924.90</td></tr> <tr> <td>b</td><td>Insurance @ 1% of capital cost</td><td>598962.45</td></tr> <tr> <td>c</td><td>Depreciation @ 3.17% of capital cost</td><td>1898710.97</td></tr> <tr> <td>d</td><td>Licence Fees for way leave permission per annum (for the calendar year 2016 as per revised Rent Schedule)</td><td>704718.00</td></tr> <tr> <td>e</td><td>Other Expenses @ 1% of capital cost</td><td>598962.45</td></tr> <tr> <td></td><td>Total cost</td><td>4999278.77</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>ROCE @ 16% of capital cost</td><td>9583399.20</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Total Revenue Requirement in ₹</td><td>14582677.97</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Pipeline usage charge per MT in ₹</td><td>28.13</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Pipeline usage charge for other edible oil pipelines laid at HDC per MT in ₹</td><td>4.95</td></tr> </tbody> </table>	Sl. no.	Particulars	Amount in ₹	1	Optimal Cargo traffic per annum in MT through this pipeline (6 days x 300 tonnes x 24 hours x 12 months)	518400	2.	Capital Cost of 5.7 km pipeline laying as given by EAL	5,98,96,245.00	3.	Average parcel size of Edible oil Vessel in MT (2016-17 edible oil parcel size at HDC)	8700		Total no. of Edible oil Vessel per annum (777600 / 8700=89.38 i.e. 89)	89	4.	Operating Cost		a	Repairs & Maintenance of Pipelines @ 2% of capital cost	1197924.90	b	Insurance @ 1% of capital cost	598962.45	c	Depreciation @ 3.17% of capital cost	1898710.97	d	Licence Fees for way leave permission per annum (for the calendar year 2016 as per revised Rent Schedule)	704718.00	e	Other Expenses @ 1% of capital cost	598962.45		Total cost	4999278.77	5.	ROCE @ 16% of capital cost	9583399.20	6.	Total Revenue Requirement in ₹	14582677.97	7.	Pipeline usage charge per MT in ₹	28.13	8.	Pipeline usage charge for other edible oil pipelines laid at HDC per MT in ₹	4.95
Sl. no.	Particulars	Amount in ₹																																																
1	Optimal Cargo traffic per annum in MT through this pipeline (6 days x 300 tonnes x 24 hours x 12 months)	518400																																																
2.	Capital Cost of 5.7 km pipeline laying as given by EAL	5,98,96,245.00																																																
3.	Average parcel size of Edible oil Vessel in MT (2016-17 edible oil parcel size at HDC)	8700																																																
	Total no. of Edible oil Vessel per annum (777600 / 8700=89.38 i.e. 89)	89																																																
4.	Operating Cost																																																	
a	Repairs & Maintenance of Pipelines @ 2% of capital cost	1197924.90																																																
b	Insurance @ 1% of capital cost	598962.45																																																
c	Depreciation @ 3.17% of capital cost	1898710.97																																																
d	Licence Fees for way leave permission per annum (for the calendar year 2016 as per revised Rent Schedule)	704718.00																																																
e	Other Expenses @ 1% of capital cost	598962.45																																																
	Total cost	4999278.77																																																
5.	ROCE @ 16% of capital cost	9583399.20																																																
6.	Total Revenue Requirement in ₹	14582677.97																																																
7.	Pipeline usage charge per MT in ₹	28.13																																																
8.	Pipeline usage charge for other edible oil pipelines laid at HDC per MT in ₹	4.95																																																

7.2. As brought out above, while furnishing the above said additional information/ clarification vide its letter dated 27 October 2017, the KOPT is seen to have again reviewed its proposal. The review is to the extent of reducing the edible oil vessel occupancy by KOPT from 108 days to 72 days in a year (i.e. 6 days x 12 months), taking into account the projected increase in POL traffic and commencement of LPG handling from middle of the year 2018, which is reported to have an impact on the edible oil traffic. In view of the said review, the tariff proposed by the KOPT at ₹ 18.75 per MT in September 2017 has now been reworked by the port at ₹ 28.13 per MT.

8. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

9. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

- (i). Deployment of Mobile Harbour Cranes at berth no. 2, 8 and 13 of Haldia Dock Complex (HDC) at the Kolkata Port Trust (KOPT) is reported to have led to an increase in the capacity for handling dry bulk cargo inside the impounded dock of HDC. In order to handle more of dry bulk cargo inside the impounded dock, the KOPT is reported to have decided to handle edible oil vessels outside the impounded dock to make room for handling additional dry bulk cargo vessels inside the impounded

dock. In this connection, the KOPT has entrusted the responsibility of laying a 16" dia pipeline from Haldia Oil Jetty (HOJ) - III to finger jetty of HDC, to one of the edible oil user viz., M/s. Emami Agrotech Limited (EAL), to be used on a common user basis.

- (ii). The KOPT has stated that the rate and other conditions of usage of such pipeline facilities should be approved by this Authority as per Land Policy Guidelines as the pipeline facilities from the jetties are used for cargo handling purpose. In this regard, it is to state that the amended Land Policy Guidelines of 2014, does not appear to have any such provision requiring this Authority to fix the rate for usage of pipelines. However, in this regard, it is to state that the KOPT envisages movement of edible oil from the HOJ to the Finger Jetty. In other words, movement of edible oil from the HOJ to the Finger Jetty is akin to landing of cargo from vessel to any wharf, quay, jetty etc. or any place within the limits of the port or port approaches. Since the operation pertains to movement of cargo from vessel at HOJ to finger jetty, it is one of the services listed under Section 42 of the Major Port Trusts (MPT) Act. In this connection, Section 42(4) of the MPT Act, 1963, read with Section 48 requires this Authority to notify the rates in respect of identified services provided by persons authorised under Section 42(3) of the MPT Act.

In cases where authorisation arrangement u/s 42(3) is other than by way of a BOT concession agreement, Clause 9 of the Tariff Policy, 2015, requires this Authority to fix ceiling rates for such services to be applied commonly at the concerned ports without reference to individual service provider. For this purpose, proposal for regulating these charges should be initiated by the concerned Major Port Trust and the tariff so fixed, will not undergo a change whether the port itself provides this service or has permitted a private operator to render the services.

The KOPT has filed its proposal for prescription of tariff under 2008 upfront tariff fixation guidelines. The application of 2008 Guidelines is with regard to fixation of upfront tariff where authorization is by way of a BOT arrangement. In the case in reference, the KOPT has granted permissions to EAL to lay one common user pipeline. The proposal of KOPT does not state that this arrangement between KOPT and EAL is a BOT arrangement. The EAL has already laid the pipeline. Further, the KOPT has proposed for prescription of tariff in its existing Scale of Rates. Tariff can be prescribed in the existing Scale of Rates of the port only when it is fixed based on the Tariff Policy, 2015. The tariff can be fixed based on the Tariff Policy, 2015, by following two approaches as mentioned therein viz., the Annual Revenue Requirement (ARR) model by taking into account the past actuals or as per the methodology prescribed in Clause 9 of the Tariff Policy. Since the proposal of the KOPT is not based on ARR model, it can be considered under Clause 9 of the Tariff Policy, 2015.

Incidentally, while dealing with the general revision proposal of KOPT in 2010, based on the proposal filed by KOPT, charges for use of Mobile Harbour Crane (MHC) at berth No. 2 and 8 of HDC was introduced in the Scale of Rates of KOPT, though KOPT had engaged contractors to provide these services on its behalf. Further, the existing Scale of Rates of KOPT revised later on after the year 2010, prescribes charges to be levied by the authorized service providers in respect of the floating pipeline handling facilities for unloading edible oil from vessels berthed at berth No.5/ off 5/ 6/ off 6, transloading facility for handling of dry bulk cargo at HDC, Cargo Transfer Charge by Floating Crane.

This case is, thus, taken up for prescription of ceiling rates for handling of edible oil through a 16" dia pipeline, following the stipulation contained in Clause 9 of the Tariff Policy, 2015. The operationalization of the tariff fixed in its Scale of Rates is in the domain of KOPT. The proposal of the Port has the approval of its Board of Trustees.

- (iii). The KOPT had filed its proposal in July 2017. Subsequently, while responding to the additional information / clarification sought by us and based on the submissions made by the users during the joint hearing, the KOPT, in its proposal of October 2017, has made some modifications in its proposal. The said modified proposal of October 2017, along with the information/ clarification furnished by the port during the processing of the case in reference, has been considered in this analysis.
- (iv). Clause 9.2 of the Tariff Policy, 2015, under which the proposal of KOPT is being considered, allows a port to adopt the tariff prescribed for the similar service/ facility prescribed in any other Major Port Trust and in its absence or if such a rate is not representative for the cargo/ service/ facility envisaged, allows the Port Trust to file a proposal with reference to optimal capacity following the principles of 2008 guidelines or based on rated capacity (with reference to the technical specification of the service/ facility/ equipment). Thus, the KOPT is generally seen to have adopted the norms from the upfront tariff guidelines of 2008, relating to the liquid bulk terminal.
- (v). Capacity:

The upfront tariff guidelines of 2008 stipulate an optimum utilization of the facility at 256 days in a year i.e. 365 days per annum @ 70% utilization. However, the port has stated that though the 3rd oil

jetty handles different types of liquid cargo, the common user pipeline can be utilized only for transportation of edible oil. Thus, in its initial proposal of July 2017, the port had presumed that jetty will be occupied by edible oil vessels on an average of 9 days a month based on the current trend of cargo handling at 3rd oil jetty, resulting in an utilisation of 108 days in a year (i.e. 9 days x 12 months). Subsequently, in its revised proposal of October 2017, the KOPT has considered the edible oil vessel occupancy at 72 days in a year (i.e. 6 days x 12 months), due to the projected increase in POL traffic and commencement of LPG handling from middle of the year 2018, which would have an impact on the edible oil traffic. Thus, considering the utilization of the pipeline for a period of 72 days in a year and taking into account the handling rate of 300 tonnes per hour, the port has determined the capacity of the pipeline at 518400 tonnes per annum (6 days x 300 tonnes per hour x 24 hours x 12 months). Based on the judgment of the port regarding the utilization of the pipeline and considering that the handling rate of 300 tonnes per hour, is the handling rate as prescribed in the Upfront guidelines for the Other Liquids, the capacity of the pipeline as assessed by the port at 518400 tonnes per annum is relied upon in the analysis.

(vi). Capital Cost:

The Capital cost for laying the pipeline as considered by KOPT is at ₹598.96 lakhs. The capital cost comprises of cost of pipeline, casing, Earth excavation, Earth filling, Pipe erection, other material costs, incidental capital costs. The capital cost as considered by the KOPT is supported by documentary evidence and is considered in the analysis.

(vii). Operating Cost:

- (a). The estimation of repairs and maintenance cost at 2% of the capital cost, Insurance cost at 1% of the capital cost and other expenses at 1% of the capital cost, is seen to be as per the norms prescribed in the upfront guidelines for liquid bulk terminal.
- (b). As per the norms prescribed in the upfront guidelines for liquid bulk terminal, depreciation is to be, inter alia, calculated as per the norms prescribed in the Companies Act. Depreciation has been estimated by the port @ 3.17% on capital cost. The KOPT has confirmed that the said depreciation is based on the provisions of the Companies Act, 2013.
- (c). The guidelines for upfront tariff stipulate that lease rent for port land is to be estimated based on the rates prescribed in the Scale of Rates of the respective Major Port Trusts. The KOPT in its proposal has considered way leave charges for the area occupied by the pipeline to the tune of 2306.95 Sq. mtrs. The licence fee considered by the KOPT is in respect of the areas covered by the Dock Interior (inside Custom bounded area) (Bare Land), Dock Zone (Bare Land) and Residential Zone.

From the calculation furnished by the port, it is seen that the KOPT has considered the two different rates for each of the zone i.e. one set of rate for the period of 3 months from 01 January 2016 to 06 April 2016 and the second set of rate for the period from 07 April 2016 to 31 December 2016, presumably on the ground that the licence fee in respect of lands at HDC have been revised and that the revised rates have come into effect from 06 April 2016. Considering that the revised licence fee has already come into effect from 06 April 2016 onwards, the question of considering the pre-revised rates does not arise. Further, considering that the revised licence fee has already come into effect from 06 April 2016, the licence fee would have got escalated by 2% per annum since April 2017 onwards. Therefore, the escalated licence fee as of the year 2017 for the Dock Interior Zone, Dock Zone and Residential Zone at HDC is considered in the analysis. However, the component of service tax, which has been considered by the port in the estimation of licence fee has not been considered in our analysis, since the tariff computation does not take into taxes and cess.

- (f) Thus, the total operating expenditure based on the above analysis works out to ₹. 49.35 lakhs as against ₹. 49.99 lakhs, as estimated by KOPT.
- (viii). The cost statement for calculation of handling charge as furnished by KOPT is modified in line with the above analysis. A copy of the modified Cost statement is attached as **Annex**.
- (ix). The total Annual Revenue Requirement (ARR) works out to ₹. 145.18 lakhs which is an aggregate of operating cost (₹. 49.35 lakhs) and 16% return on capital cost (₹. 95.83 lakhs), as against the Annual Revenue Requirement estimated by the port at ₹. 145.83 lakhs as estimated by KOPT.

- (x). The KOPT has envisaged recovery of the entire assessed ARR from the optimal capacity of edible oil using the pipeline. Accordingly, considering the modified ARR at ₹.145.18 lakhs and the optimal capacity of the facility at 5.18 lakh tonnes, the rate works out to ₹.28.00 per tonne, instead of ₹.28.13 per tonne as proposed by the KOPT.
- (xi). Considering that the rate of ₹ 28.00 per tonne as proposed by the KOPT is for a 16" dia edible oil pipeline measuring 5.70 kms., the KOPT in its proposal has also proposed a pipeline usage charge of ₹.4.95 per MT (₹ 28.00 per tonne/5.70 kms.) for handling of edible oils on common usage basis, other than through 16" dia pipeline. The port is of the view that in case of pipeline of dia which is lower than 16", the capital cost is also expected to come down and that at the same time, the flow rate is also expected to come down, wherein the cost per ton per km is expected to remain same.

The submissions made by KOPT are not substantiated with any calculations. The quantum of change in the dia of the pipeline need not be directly proportional to the quantum of change in the capital cost and the flow rate. Hence, this Authority is not in a position to approve the said charge as proposed by the Port. However, the KOPT is advised to come up with a suitable proposal for fixation of charges for use of other than 16" dia pipelines, well in advance before commissioning the facility.

- (xii). By formulating the proposal under the tariff guidelines of 2008, the KOPT has proposed indexation of base tariff to the extent of 60% of WPI to cover inflation. The entire Scale of Rates (SOR) of KOPT including the rate approved now will be due for review after one year say 31 March 2019. It is noteworthy that the KOPT has also proposed approval of tariff for a period of one year say 31 March 2019. Therefore, the aspect of indexation can be reviewed at that point of time depending on the situation prevailing then. The performance standard as proposed by the KOPT at 300 tonnes per hour is prescribed.
- (xiii). Orders passed by this Authority generally come into effect prospectively after expiry of 30 days from the date of Gazette Notification. Since a tariff arrangement already prevails, a lead period of 15 days is found sufficient. Accordingly, the pipeline usage charges shall come into effect after expiry of 15 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India. Further, the tariff for pipeline usage has been proposed to be incorporated by KOPT in the existing Scale of Rates of KOPT under Section 4 of Part IX - Charges for authorized service providers. As such, the validity of the pipeline usage charges approved now shall be co terminus to the validity of existing Scale of Rates of KOPT, as proposed by the Port.

10.1 In the result, and for the reasons given above, and based on collective application of mind, incorporation of the following provision as Section – 4 under Part – IX – Charges for Authorised Service Providers, in the existing Scale of Rates of KOPT, is approved:

“Section – 4: Usage charges for 16" dia Pipeline between Haldia Oil Jetty (HOJ) – III to Finger Jetty at Haldia Dock complex (HDC) of KOPT:

- (i). The definition of “Edible oil”. “Edible oil” means PLMOC, SBO, SOYA OIL etc. (both crude and refined).
- (ii). Charges for handling of edible oil through common user 16" dia edible oil pipelines from 3rd oil jetty to finger jetty:

Sr. no.	Commodity	Rate in ₹. per MT
1.	Pipeline usage charges	28.00

- (iii). The Performance Standard for handling the edible oil is 300 tonnes per hour.

10.2. The KOPT is advised to suitably incorporate the above provisions in its Scale of Rates.

10.3. The said charges shall be effective after expiry of 15 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India and its validity shall remain co-terminus to the validity of the existing Scale of Rates of KOPT i.e. upto 31 March 2019. The approval accorded shall automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.III/4/Exty./314/17]

Annex

CALCULATION OF TARIFF FOR HANDLING EDIBLE OIL THROUGH 16" DIA COMMON USER PIPELINE LAID FROM HOJ-III UPTO FINGER JETTY OF HALDIA DOCK COMPLEX, KOLKATA PORT TRUST

Sl. No.	Particulars	As per KOPT initial Proposal of July 2017	As per KOPT revised Proposal of September 2017	As per KOPT revised Proposal of October 2017	As Per TAMP Modifications
		₹.	₹.	₹.	₹.
1	Optimal capacity per Annum (In MT)	777600	777600	518400	518400
2	Capital Cost	59896245.00	59896245.00	59896245.00	59896245.00
3	Average Parcel Size. Of Edible Oil Vessels	8700	8700	8700	8700
4	Estimated No. of Edible Oil Vessels per annum	89	89	60	60
5	Operating Cost				
	a) Repairs and Maintenance of Pipelines (2% of the Capital Cost)	1197924.90	1197924.90	1197924.90	1197924.90
	b) Insurance (1% of the Capital Cost)	598962.45	598962.45	598962.45	598962.45
	c) Depreciation (3.17% of Capital Cost)	1898710.97	1898710.97	1898710.967	1898710.967
	d) Way leave permission charges (Note 1)	704718.00	704718.00	704718	640389
	e) Other Expenses (1% of Capital Cost)	598962.45	598962.45	598962.45	598962.45
	f) Fuel cost (120 ltrs per vessel x 57.23 per ltr.)	611216.40	-	-	-
	Total (5)	5610495.17	4999278.77	4999278.77	4934949.97
6	Return on Capital Employed (ROCE) (16% of Capital Cost)	9583399.20	9583399.20	9583399.20	9583399.20
7	Annual Revenue Requirment [5 + 6]	15193894.37	14582677.97	14582677.97	14518349.17
	a) Cargo Handling Charges through Pipeline (95%)	14434199.65	-	-	-
	b) Miscellaneous Charges (5%)	759694.72	-	-	-
8	Pipe Line Charges per Metric Tonne	18.56	18.75	28.13	28.00
9	Pipe Line Chages for other Edible Oil Pipelines laid at HDC per Metric Tonne	-	3.30	4.95	-
10	Misc. Charges (Pigging per vessel)	8535.90	-	-	-

NOTE 1:

Zone	Area of Pipeline coverage in respective zone (Sq. Mtrs)	Rate applicable as in 2017 as per KOPT Rent Schedule (Rs. Per 100 Sq. Mtrs per month)	Way-Leave Permission Fees (₹.)
Dock Interior Zone	1548.93	2680.56	498240
Dock Zone	375.96	1488.18	67140
Residential Zone	382.06	1636.08	75010
			640389